● वर्ष : 17 ● अंक : 202 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

बुधवार 13 मई 2026

हिमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

एजेंसी। गुवाहाटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि, असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की लगातार तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है। वर्ष 2016 में पहली बार भाजपा ने असम में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में सफल हुई थी। गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित भव्य समारोह में डॉ. सरमा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत राजग शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ली। उनके साथ भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, असम गण परिषद (अगप) के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के चरण बोडो ने मंत्री पद की शपथ ली। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में राजग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें भाजपा को 82 सीटें मिलीं, जबकि सहयोगी दलों अगप को 10 तथा बीपीएफ को 10 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान पूरे राज्य से पहुंचे लाखों लोग जय श्रीराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय आई असम आदि के नारे लगाते रहे, जिससे पूरे माहौल में उत्साह देखा गया। समारोह में महिलाओं की भी बड़ी सख्या में मौजूदगी देखी गयी। भारी संख्या में पहुंचे लोगों की सुविधा के लिए पंडाल के अलग-अलग हिस्सों में बड़े-बड़े एलईडी डिस्प्ले लगाए गये थे। डॉ. हिमंत बिस्व सरमा, रामेश्वर तेली, अजंता नेओग तथा असम गण परिषद (अगप) विधायक अतुल बोरा ने असमिया भाषा में शपथ ग्रहण किया, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के विधायक चरण बोडो ने बोडो भाषा में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में आज मुख्यमंत्री सफेद धोती-कुर्ता एवं गले में असमिया गमोछा धारण कर नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के सभी स्तर के पदाधिकारियों के साथ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी थी।

मोदी के विजन, नीति से असम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को गुवाहाटी में आयोजित असम की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एवं मंत्री पद की शपथ लेने वाले उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और नॉर्थ-ईस्ट को भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में स्थापित करने की उनकी नीति के परिणामस्वरूप आज असम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक हैट्रिक जन-विश्वास और स्थिरता का प्रतीक बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में जो मान-सम्मान और पहचान प्रधानमंत्री ने दी है, उसे आज जन-जन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। असम का प्रचंड जनादेश इसकी स्पष्ट पुष्टि करता है। सबका साथ, सबका विकास के संकल्प ने असम में सेवा और सुशासन के नए दौर को और अधिक सशक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार जनाकांक्षाओं को पूरा करेगी और समृद्ध एवं विकसित असम के संकल्प को साकार करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगी।

असम में लगातार तीसरी बार राजग सरकार बनने पर प्रधानमंत्री ने सरमा को दी बधाई

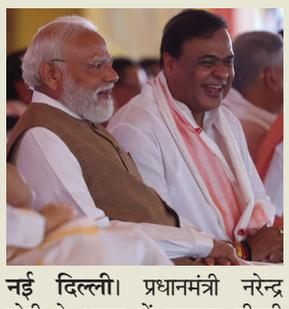

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के गठन पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमंता सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है और राज्य के विकास के लिए कई परिवर्तनकारी कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, "असम के लिए आज एक विशेष दिन है। लगातार तीसरी बार राजग सरकार ने सत्ता संभाली है। मैं डॉ. हिमंत बिस्व सरमा को पदभार ग्रहण करने पर बधाई देता हूं। उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है और राज्य के लिए कई अग्रणी कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कार्यकाल के लिए उनकी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने असम सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के प्रयासों से असम के विकास की गति और मजबूत होगी। मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "मैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग को असम सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई देता हूं। राज्य के विकास की यात्रा को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रभावी कार्यों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

संक्षिप्त समाचार

साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आई4सी और आरबीआईएच के बीच एमओयू, एआई से होगी अवैध खातों की पहचान

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार 'साइबर सुरक्षित भारत' के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में 'म्यूल अकाउंट' बड़ी बाधा हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नई व्यवस्था साइबर धोखाधड़ी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग प्रणाली में अवैध खातों (म्यूल अकाउंट) पर रोक लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, "मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत के लिए अथक प्रयास कर रही है। म्यूल अकाउंट साइबर अपराधों पर रोक लगाने में बड़ी बाधा हैं। आज गृह मंत्रालय के आई4सी ने आरबीआईएच के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे साइबर धोखाधड़ी से लड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आई4सी के 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' डेटा को एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम से जोड़कर छिपे हुए म्यूल अकाउंट की तेजी से पहचान कर उन्हें समाप्त किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सीएसआईआर-सीबीआरआई की 13 स्वदेशी तकनीक उद्योगों को हस्तांतरित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीबीआरआई), रुड़की द्वारा विकसित 13 स्वदेशी तकनीक को उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को हस्तांतरित किया गया। इनमें अग्नि सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण, ऊर्जा दक्षता और अधोसंरचना संरक्षण से जुड़ी नवाचार शामिल हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रद्यौगिकी मंत्रालय के अनुसार, आज यहां सीएसआईआर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रुड़की में सीएसआईआर-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) रे मुख्य वैज्ञानिक डॉ. अजय चौरसिया ने कहा कि उद्योग उन्मुख तकनीक हस्तांतरण से देश में नवाचार आधारित विकास को गति मिलेगी। सीएसआईआर-सीबीआरआई के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर यह आयोजन विशेष महत्व रखता है और स्वदेशी तकनीकों का उद्योगों को हस्तांतरण भारत के अनुसंधान तंत्र की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम है। कार्यक्रम में लकड़ी और उसके विकल्पों के लिए अग्निरोधक पारदर्शी कोटिंग, आरसीसी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आईपीएन कोटिंग तकनीक, कम कार्बन ईंट निर्माण तकनीक, हाइब्रिड सौर-सहायित हीट पंप प्रणाली और दीवार सुरक्षा के लिए प्रीफैब्रिकेटेड उच्च शक्ति स्टील कॉर्ड तकनीक का हस्तांतरण किया गया।

जमानत मामलों को हर हफ्ते या कम से कम दो हफ्ते में एक बार जरूर लिस्ट करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में लंबित जमानत मामलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हाईकोर्ट में सालों से लंबित हजारों जमानत याचिकाएं स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार का उल्लंघन करती हैं। जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तय सिस्टम बनाना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सबसे कम समय में फैसले लेने के लिए सराहना की। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जमानत याचिकाओं की भारी संख्या लंबित है, पीठ ने इस तथ्य की सराहना की कि वहां लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि न्यायाधीशों को प्रतिदिन करीब 200 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करनी पड़ती है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सोमवार को सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जमानत याचिकाओं की सुनवाई तेजी से और नियमित तरीके से हो। जमानत के मामलों को हर हफ्ते या कम से कम दो हफ्ते में एक बार जरूर लिस्ट किया जाए। इसके लिए ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम तैयार करने को कहा ताकि किसी मामले की सुनवाई सिर्फ तारीख पर तारीख तक सीमित न रहे। वर्तमान में अदालतों की सामान्य प्रक्रिया यह है कि वे आरोपी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हैं और संबंधित राज्य सरकार, जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष से जवाब मांगते हैं।

लाखों छात्रों को झटका: नीट यूजी 2026 रद्द, पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2026 को पेपर लीक के गंभीर आरोपों के चलते रद्द किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस संवेदनशील मामले की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश दिए हैं, इससे मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। यह परीक्षा रविवार, 3 मई 2026 को पूरे देश में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। एनटीए ने स्पष्ट किया कि 8 मई 2026 को ही विचाराधीन मामलों को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था। एजेंसी ने राष्ट्रीय परीक्षाओं के निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसके अनुरूप यह कदम उठाया गया है। एनटीए ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से की गई जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए जांच निष्कर्षों के आधार पर, तथा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय हुआ है। अब यह परीक्षा अलग से अधिसूचित नई तिथियों पर पुनः आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक की आशंकाएं मुख्य रूप से राजस्थान से सामने आई थीं, जहां से कई चौंकाने वाले दावे किए गए थे। राजस्थान विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने इन आरोपों की विस्तृत जांच शुरू की थी। एसओजी को एक हस्तलिखित सुझाव पत्र मिला है, जिसके करीब 120 प्रश्न नीट के वास्तविक प्रश्नपत्र से हूबहू मेल खाते हैं। इसमें करीब 90 जीव विज्ञान के प्रश्न और 30 रसायन विज्ञान के प्रश्न शामिल थे, जो लीक के दावों को बल देते हैं। इस फैसले ने उन लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है जिन्होंने महीनों तक इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत की थी। सीबीआई जांच से उम्मीद की जा रही है कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

प्रसाद की तरह नौकरी बांटने वाले पूर्व मंत्री बोस गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ता में भाजपा के आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य के पूर्व दमकल एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। कथित नगर निगम भर्ती घोटाले के मामले में करीब साढ़े 10 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह कड़ा कदम उठाया। सुजीत बोस नई सरकार के कार्यकाल में गिरफ्तार होने वाले पहले कद्दावर टीएमसी नेता हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रसाद की तरह अयोग्यों को भी नौकरियां बांट दीं। पूछताछ के दौरान जब दिल्ली मुख्यालय से हरी झंडी मिली, तो रात 9:15 बजे उन्हें आधिकारिक तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही सुजीत बोस की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनके परिजन दवा लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों का आरोप है कि बोस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनके बयानों में काफी विसंगतियां पाई गईं।

चीन को सोचना चाहिए कि आतंकवादियों की मदद करने से उसकी कितनी इज्ज़त बढ़ी: भारत

नई दिल्ली। भारत ने चीन द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान पाकिस्तान को सहायता दिये जाने की स्वीकारोक्ति पर आज अफसोस जाहिर किया और कहा कि उसे सोचना चाहिए कि आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों में मदद करने से उसकी वैश्विक साख एवं प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में चीन की स्वीकारोक्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन ने उन्हीं बातों की पुष्टि की है जो भारत को पहले से पता हैं। जायसवाल ने कहा, "हमने इन रिपोर्टों को देखा है और यह उन्हीं तथ्यों की पुष्टि करती हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता था। प्रवक्ता ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपा-तुला जवाब था। इसका उद्देश्य उस आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, जो न केवल पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, बल्कि पाकिस्तान से और उसके इशारे पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों पर निर्भर है जो स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में चीन ने स्वीकार किया है कि उसने भारत के ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान पाकिस्तान को सीधे तौर पर सहायता प्रदान की थी। चीनी विमानन उद्योग संस्था के इंजीनियरों ने माना कि वे पाकिस्तान में जे-10सीई लड़ाकू विमानों की तकनीकी सहायता के लिए मौजूद थे।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से बाजार में हड़कंप

आशंकाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित आर्थिक संकट, ईंधन की बढ़ती खपत, विदेशी निर्भरता तथा घरेलू संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर व्यक्त चिंताओं के बाद देश के बाजारों में बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट, सोने और आभूषण कारोबार में चिंता तथा महंगाई को लेकर आम लोगों की आशंकाएं यह संकेत दे रही हैं कि देश आर्थिक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रहा है। भारत लंबे समय से ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भर रहा है। यदि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति गंभीर होती है, तो सबसे पहला प्रभाव तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा।

पहले से ही महंगे पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस से परेशान जनता के सामने महंगाई की नई सुनामी खड़ी हो सकती है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्यान्न, सब्जियों, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ना लगभग तय माना जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, विदेश यात्राओं को रोकने और इसी के साथ ही भोजन में तेल कम से कम उपयोग करने पर जोर दिए जाने को लोग आने वाले कठिन समय की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।

दरअसल कोरोना महामारी का अनुभव अभी भी देशवासियों की सामूहिक स्मृति में ताजा है। उस समय लॉकडाउन, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक ठहराव ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था। यदि वर्तमान संकट की तुलना उसी दौर से की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती ही बढ़ती है। बाजारों की घबराहट केवल आर्थिक आंकड़ों का परिणाम नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ते ही शेयर बाजार गिरने लगता है और आम जनता खर्च रोककर बचत की ओर बढ़ती है। सोने की खरीद टालने की अपील ने भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भारत में आभूषण उद्योग करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा है। यदि उपभोक्ता सोने की खरीद कम करते हैं, तो छोटे ज्वेलर्स, कारीगरों और संबंधित व्यापारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही कारण है कि व्यापारिक संगठनों में चिंता बढ़ी है। हालांकि सरकार का उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत और अनावश्यक आयात कम करना हो सकता है, लेकिन ऐसे कदमों के सामाजिक और रोजगार संबंधी प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वर्तमान संकट का एक बड़ा पहलू विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार असंतुलन भी है। भारत का आयात लगातार निर्यात से अधिक रहा है। यदि तेल आयात पर खर्च बढ़ता है और विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालते हैं, तो रुपये पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। रिजर्व बैंक को रुपये को संभालने के लिए डॉलर बेचने पड़ सकते हैं। प्रवासी भारतीयों से आने वाली विदेशी मुद्रा में कमी और वैश्विक मंदी की आशंका इस संकट को और गंभीर बना सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौर सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विपक्ष पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। यदि महंगाई लगातार बढ़ती है और जनता की क्रय शक्ति घटती है, तो इसका सीधा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि आर्थिक संकट अक्सर सामाजिक असंतोष को जन्म देता है। ऐसे समय में केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को ठोस आर्थिक रणनीति, पारदर्शी संवाद और राहत उपायों के साथ आगे आना होगा। विपक्ष को भी राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर रचनात्मक सहयोग की भूमिका निभानी चाहिए।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

टाटा ने फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के सहयोग से तैयार किया पहला सी-295 एयरक्राफ्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

इसी तरह 39 अन्य विमानों का निर्माण दस वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम भारत में ही करेगा

फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के सहयोग से गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने फाइनल असेंबली लाइन में पहला सी-295 एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह भारत में सैन्य परिवहन का पहला एयरक्राफ्ट है, जो भारतीय वायुसेना के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को पूरा करता है। यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने देश में पूरी मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन बनाई और चालू की है। यह कार्यक्रम 2021 में किए गए 21 हजार 935 करोड़ के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट डील के तहत वायु सेना के लिए फ्रांसीसी कंपनी एयरबस की साझेदारी में चलाया जा रहा है। फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 24 सितंबर 2021 को 56 सी-295 सैन्य परिवहन विमानों का सौदा फाइनल हुआ था। इसी सौदे के तहत यह पहला विमान स्पेन में ही तैयार करके वायु सेना को आपूर्ति भी कर दिया गया है। यह पहला सी-295 परिवहन विमान 20 सितम्बर 2023 को वडोदरा के वायु सेना स्टेशन पर उतरा था। इस विमान को ग्रुप कैप्टन पीएस नेगी फ्रांस से मिस्र और बहरीन होते हुए उड़ाकर भारत लाये थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना के परिवहन बेड़े में शामिल किया था। भारतीय वायु सेना के लिए स्पेन में तैयार किया गया पहला सी-295 सैन्य परिवहन विमान 13 सितंबर को एयरबस कंपनी ने भारतीय वायु सेना के तत्कालीन प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को स्पेन के सेविले में सौंपा था। सी-295 विमान की चाबी मिलने के बाद उसी दिन एयर चीफ ने स्पेन में खुद यह विमान उड़ाकर इसकी क्षमता परखी थी। समझौते के मुताबिक़ कंपनी को 16 विमान स्पेन में तैयार करके भारत को 'फ्लाइंग मोड' में आपूर्ति करना है, जबकि अन्य 40 विमानों का निर्माण दस वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम भारत में ही करेगा। सभी 40 भारतीय-निर्मित एयरक्राफ्ट अगस्त 2031 तक आपूर्ति किये जाने की उम्मीद है। हैदराबाद की मुख्य उपकरण असेंबली में एयरक्राफ्ट के उपकरण तैयार करके वडोदरा प्लांट में असेंबल किए जाते हैं।

ख़ास ख़बर

आरके फैमिली ट्रस्ट विवादः रानी कपूर पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, ट्रस्ट में दखल रोकने की मांग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल कर इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया होने तक प्रिया कपूर और दूसरे लोगों को आरके फैमिली ट्रस्ट के कामकाज में दखल देने से रोकने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले को देखने पर महाभारत भी बहुत छोटी लगेगी। हम इस मामले को देखेंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 14 मई को करने का आदेश दिया। रानी कपूर ने अपनी नई अर्जी में आरके फैमिली ट्रस्ट की 18 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग पर भी रोक लगाने की मांग की है। ये मीटिंग रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नोटिस पर बुलाई गई थी, जिसका विवादित संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर कब्जा बताया जाता है। रानी कपूर की अर्जी में कहा गया है कि इस मीटिंग का मुख्य मकसद बोर्ड में अपनी पसंद के नये डायरेक्टर को नियुक्त करना है।सात मई को उच्चतम न्यायालय ने रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच सोना ग्रुप पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया।संजय कपूर की मां रानी कपूर ने पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और उसके प्रबंधन की परिस्थितियां सवालों के घेरे में हैं। याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया। इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थी, लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी।

सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल कोयला घोटाला मामले में अनूप माजी को जारी किया नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपित अनूप माजी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने माजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।अनूप माजी को 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले की जांच के लिए 2025 में आई-पैक के कोलकाता स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। इसी छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वे कई डिजिटल सबूत अपने साथ लेकर चली गईं। इस मामले में ईडी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है।मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि माजी फरार चल रहा है और इस अपराध में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि अनूप माजी इस मामले का किंगपिन है जिस पर 2700 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। सुनवाई के दौरान माजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि माजी ने जांच में पूरी मदद की है। वो 23 बार पूछताछ के लिए बुलाने पर गया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला कारोबार के मामले में 2 अगस्त 2022 को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में 2742 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया गया है।

टीवीके विधायक सेतुपति ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायक सिनीवासा सेतुपति ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मतदान करने से रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। सेतुपति के निर्वाचन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सेतुपति की जीत महज एक वोट से हुई है।इस मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका पर कल यानि 13 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। सेतुपति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तिरुपत्तुर से एक वोट से जीत हासिल की थी। सेतुपति के निर्वाचन को डीएमके उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक पोस्टल बैलट की गिनती इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो दूसरे विधानसभा सीट के लिए भेज दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट से पत्रकार वरदराजन को राहत, ओसीआई अर्जी खारिज करने का आदेश रद्द

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) की अर्जी को खारिज करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने केंद्र सरकार के आदेश को कानून सम्मत नहीं कहा है। कोर्ट वरदराजन की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर कल यानि 13 मई को सुनवाई करेगा।सिद्धार्थ वरदराजन अपना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) के दर्जे को ओसीआई में तब्दील करवाना चाहते हैं। अब पीआईओ का दर्जा अस्तित्व में नहीं है और उसे ओसीआई में ही शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को वरदराजन की ओसीआई की अर्जी को अस्वीकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार का निर्देश लेने चाहते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि निर्देश की कोई जरुरत नहीं है, इस आदेश में कानून का पालन नहीं किया गया है इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। वरदराजन ने अमेरिकी नागरिकता ले रखी है और वो पीआईओ कार्डधारक भी हैं। सभी पीआईओ कार्ड 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर कर गए और वे भारत में प्रवेश करने या रुकने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि पीआईओ को ओसीआई में ही तब्दील कर दिया गया। वरदराजन ने कहा कि उन्होंने ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन दिया था। उनका पीआईओ कार्ड 2032 तक के लिए वैध था, लेकिन अब पीआईओ कार्ड अस्तित्व में ही नहीं है। याचिका में कहा गया है कि पीआईओ कार्ड को ही ओसीआई कार्ड माना जाता है लेकिन वरदराजन ओसीआई का फिजिकल कार्ड लेना चाहते थे, लेकिन 2 अप्रैल को उनकी यह अर्जी अस्वीकार कर दी गई।

नर्सें अपनी ममता और देखभाल से मरीज को नया जीवन देती हैं : रेखा गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अलग-अलग वार्डों में जाकर नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। यह जानकारी मंगलवार को एक विज्ञप्ति के जरिए साझा की गई। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बेहद आत्मीयता के साथ नर्सों से संवाद करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। डॉक्टर यदि उपचार करते हैं तो नर्सें अपनी ममता और देखभाल से मरीज को नया जीवन देती हैं। कठिन परिस्थितियों में आपका धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अस्पताल में कार्यरत विभिन्न राज्यों (केरल, राजस्थान, पंजाब आदि) के नर्सिंग स्टाफ से विशेष तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने-कोने से आए इन जांबाज स्वास्थ्यकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना की रिकॉर्ड वृद्धि की है। उनको मिलने वाली राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 13,150 कर दी गई है। इस फैसले से 180 नर्सिंग इंटर्न्स को बड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के वर्क कल्चर को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मरीजों की सेवा में दिन-रात समर्पित रहने वाले नर्सिंग स्टाफ का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने सभी नर्सों को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सेवा भावना के लिए उनका हौसला बढ़ाया।

बृजभूषण सिंह मामले में एसआईटी सदस्य का बयान दर्ज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य का बयान दर्ज किया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी के 15 एवं 19 मई को बयान दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में अभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल 2024 को बृजभूषण की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

फोर्टिस मानेसर में जनरल सर्जरी विभाग ने 50+ रोबोट-असिस्टेड सर्जरी पूरी की, अस्पताल ने अब तक लगभग 150 रोबोटिक प्रक्रियाओं को दिया अंजाम

» हर्निया और गॉलब्लैडर की जटिल सर्जरी अधिक सटीक और कम से कम दर्द के साथ हुई संपन्न, मरीजों के मामले में बेहतर परिणाम

लोकतंत्र की शान

मानेसरः उन्नत सर्जिकल लाभ और नेक्स्ट-जेन मिनीमॅली इन्वेसिव केयर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, फोर्टिस हॉस्पीटल मानेसर के जनरल सर्जरी विभाग ने अब तक 50+ रोबोट-असिससस्टेड सर्जरी की हैं, और इस प्रकार अस्पताल की विभिन्न स्पेशयलिटीज में 150 से अधिक रोबोटिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह उपलब्धि कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं जैसे पेट की भीतरी सतह के रीकंस्ट्रक्शन, हर्निया रिपेयर, और गॉलब्लैडर सर्जरी आदि को एडवांस रोबोटिक-असिस्टेड प्रक्रियाओं के मामले में अस्पताल की लगातार बढ़ रही विशेषज्ञता दर्शाती है। इस उपलब्धि को दर्ज कराने के साथ ही, अस्पताल ने ऐसी कई जटिल और सफल प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी जिन्हें रोबोट-असिस्टेड सर्जरी की मदद से पूरा किया गया है। इनमें एक मामला, 61-वर्षीय महिला का है जो पेट में बड़े और जटिल किस्म के इरिड्यूसिबल हर्निया की रोबोट की मदद से की गई सर्जरी का है। यह प्रक्रिया इस वजह से काफी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि मरीज अन्य कई रोगों जैसे लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया और हाइपोथॉयराइडिज़्म से भी ग्रस्त थीं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी की सहायता से, अस्पताल के सर्जनों ने काफी सटीक तरीके से रिपेयर और बेहतर कंट्रोल तथा कम से कम रक्तस्राव सुनिश्चित करते हुए कई अन्य जटिलताओं जैसे मलमार्ग बाधित होने और ऊतकों को नुकसान पहुंचने से भी बचाया। यह सर्जरी लगभग दो घंटे चली और मरीज की हालत अब स्थिर है।

प्रो. सलीम इंजीनियर ने NEET 2026 में हुई अनियमितताओं की निंदा करते हुए स्वतंत्र जाँच और कड़ी कार्रवाई की माँग की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के तहत मरकजी तालीमी बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने एनईईटी यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं की कड़ी निंदा की है जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता को बनाए रखने में विफल रहने तथा चिकित्सा क्षेत्र में देश की सेवा करने के आकांक्षी लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ज़िम्मेदार ठहराया। मीडिया को जारी एक बयान में तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, "हम नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई उन अनियमितताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिनके कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नीट परीक्षा देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है जिसमें हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। एक ऐसे 'गेस पेपर' जिसमें वास्तविक परीक्षा से मेल खाने वाले सवालों की बड़ी संख्या शामिल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित प्रक्रिया की निष्पक्षता में एक गंभीर सेंध का संकेत देता है। अनौपचारिक नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऐसे बेहद सटीक 'गेस पेपर्स' की बिक्री और बड़े पैमाने पर उनका सर्कुलेशन, संगठित कदाचार की ओर इशारा करता है। इस तरह के पेपर लीक परीक्षा प्रणाली में जनता के भरोसे को कमज़ोर करते हैं, और छात्रों व अभिभावकों के बीच योग्यता तथा समान अवसर को लेकर विश्वास का गंभीर संकट पैदा करते हैं। हम इस विफलता के लिए सरकार और NTA को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार मानते हैं, जिसने लाखों NEET उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने आगे कहा, "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने और उसे दोबारा आयोजित करने का फ़ैसला, साथ ही सरकार का इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने का कदम, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की गंभीरता की साफ़ तौर पर स्वीकारोक्ति है। हालाँकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था लेकिन इसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए भारी मानसिक कष्ट और अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस उल्लंघन के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनके साथ यथासंभव कठोरता से निपटा जाना चाहिए, ताकि यह एक मज़बूत निवारक के रूप में काम कर सके। इसके साथ ही NTA और शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वालों को इन असफलताओं की जवाबदेही स्वीकार करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नैतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।"

एक महीने पहले मिल सकेगी मानसून की सटीक जानकारी, एआई आधारित सेवाओं की शुरुआत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। देश में मौसम पूर्वानुमान अब पहले से ज्यादा आधुनिक और सटीक होने जा रहा है। मंगलवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित दो नई मौसम पूर्वानुमान सेवाओं की शुरुआत की। इन सेवाओं के जरिए अब लोगों को गांव और ब्लॉक, स्थानीय स्तर तक मानसून की सटीक जानकारी चार हफ्ते पहले मिल सकेगी। यह जानकारी हर बुधवार को जारी होगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष सेवा की शुरुआत की है जिसके तहत उन्हें एक किलोमीटर के अंदर दस दिन पहले मौसम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इन प्रणालियों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।इन दोनों सेवाओं की शुरुआत के मौके पर मंगलवार को मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पहला एआई सिस्टम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान 10 दिन पहले तक देगा। यानी अगर मानसून केरल में दस्तक देगा तो अगले 10 दिनों में मानसून किस-किस प्रदेश के कौन से गांव तक पहुंचेगा इसकी सटीक जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इससे 16 राज्यों और 3000 से ज्यादा जिलों में किसानों और प्रशासन को समय रहते मौसम की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए एक किलोमीटर रिजॉल्यूशन वाला हाई स्पेशियल रेनफॉल फोरकास्ट सिस्टम भी शुरू किया गया है। यह सिस्टम 10 दिन पहले तक बेहद सटीक बारिश का पूर्वानुमान देगा।इस नई तकनीक में एआई, स्टैलाइट डेटा, डॉपलर रडार और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मौसम पूर्वानुमान की सटीकता काफी बढ़ेगी।इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग डेढ़ दशक पहले देश में मुश्किल से 16 से 17 डॉप्लर मौसम रडार थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 50 हो गई है और मिशन मौसम के तहत 50 और रडार लगाने की योजना है। अवलोकन नेटवर्क, स्वचालित मौसम स्टेशनों, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों और डिजिटल प्रसार प्लेटफार्मों के इस विस्तार से पूरे देश में मौसम पूर्वानुमान क्षमता और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में काफी सुधार हुआ है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में भीषण मौसम संबंधी घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 40 प्रतिशत सुधार हुआ है। पिछले पांच वर्षों में चक्रवात के मार्ग, तीव्रता और भूस्खलन के 72 घंटों के पूर्वानुमान में लगभग 30 से 35 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जबकि मौसमी पूर्वानुमान त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आई है।डॉ. सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि के कारण सटीक और समय पर पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।मंत्री कहा कि मोदी सरकार ने देश में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई परिवर्तनकारी पहल की हैं। मिशन मौसम, रडार नेटवर्क का विस्तार, अवलोकन प्रणालियों को मजबूत करना, डेटा संचार अवसंरचना का आधुनिकीकरण और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं का संवर्धन सामूहिक रूप से एक अधिक मजबूत और प्रौद्योगिकी-आधारित पूर्वानुमान प्रणाली की दिशा में योगदान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन, आईआईटीएम पुणे के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव, आईएमडी, आईआईटीएम और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे।

'ऑपरेशन विश्वास' 12,600 से अधिक मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए : तरनजीत सिंह संधू

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उपास्थिति में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत 12,600 से अधिक चोरी के बरामद मोबाइलों को दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनके मालिकों को लौटाए गए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज नागरिकों के चेहरों पर खुशी देखकर बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि 12,600 से अधिक बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए। 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत चलाया गया यह बड़ा अभियान, हर व्यक्ति के लिए प्रभावी ढंग से शासन और पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित होकर, हम प्रौद्योगिकी को सशक्तिकरण और विश्वास के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज मोबाइल फोन किसी व्यक्ति की यादों, काम और डिजिटल पहचान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसे वापस सौंपना एक अधिक उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है।उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को उनके अथक प्रयासों और इस वर्ष 74 फीसद की प्रभावशाली वसूली दर हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, 'इससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि गैरकानूनी रूप से ली गई किसी भी वस्तु का पता लगाया जाएगा और उसे वापस लौटाया जाएगा।' उपराज्यपाल ने कहा कि सुरक्षित, आधुनिक और कानून के शासन में दृढ़ विकसित दिल्ली का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है।

एआई इंटीग्रेशन से इंडिया पोस्ट की सेवा गुणवत्ता में सुधारः पेम्मासानी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भारतीय डाक विभाग के एपीटी 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करते हुए कहा कि यह प्रणाली आधुनिक लॉजिस्टिक्स और सेवाओं के केंद्र में बदल रही है। एपीटी 2.0 शाखा कार्यालयों को रीयल-टाइम इंटेलिजेंस प्रदान कर रहा है, जिससे स्थानीय मांग का विश्लेषण, प्रदर्शन की निगरानी और तेज, डेटा-आधारित निर्णय लेना संभव हो रहा है। संचार मंत्रालय ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के एकीकरण से डाक विभाग बड़े पैमाने पर परिचालन डेटा का विश्लेषण कर पा रहा है, परिणामों का पूर्वानुमान लगा रहा है, नियमित कार्यों का स्वचालन कर रहा है और सेवा वितरण को अधिक कुशल बना रहा है। मंत्री ने कहा कि इससे सेवा वितरण तेज हुआ है, मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है, निर्णय-निर्माण बेहतर हुआ है और ग्राहक संतुष्टि बढ़ी है। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि एपीटी 2.0 का व्यावसायिक प्रभाव भी स्पष्ट है। यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में ग्राहकों तक बेहतर पहुंच बनाने, शाखा स्तर पर सेवा अपनाने में सुधार करने और समय पर डेटा-आधारित संपर्क के जरिए नए राजस्व अवसर खोलने में मदद कर रहा है। यह परिवर्तन डाक विभाग को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स रीढ़ की हड्डी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी स्तर से इसके क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है, जिससे संगठन में पारंपरिक प्रणाली से कॉर्पोरेट-शैली की तकनीक-आधारित संस्कृति की ओर बदलाव हो रहा है। डिजिटल पुश से डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मजबूत हुई है, जिससे भरोसेमंद और भविष्य-उन्मुख सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

संक्षिप्त समाचार

संभल पुलिस का सघन फुट पेट्रोलिंग अभियान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की हुई चेकिंग

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी : संभल/ सिरसी हजरत नगर गढ़ी में संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह एवं सिरसी चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, चौराहों एवं संवेदनशील इलाकों में सघन फुट पेट्रोलिंग की गई। फुट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन चेकिंग करते हुए लोगों से संवाद स्थापित किया तथा सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों एवं राहगीरों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं सिरसी चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल ने कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। पुलिस की इस सक्रिय कार्यवाही से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ आम नागरिकों में विश्वास का माहौल देखने को मिला।

विश्व प्रसिद्ध दरगाह जोगीपुरा में 21 मई से सालाना मजालिस का आगाज़ होगा

जोगीपुरा में सालाना मजलिसों की तैयारियां जोरों पर

लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद , बिजनौर । नजीबाबाद शिया धर्म गुरु मौलाना शबाब नक़वी प्रशासक दरगाह ने बताया कि आने वाली सालाना मजालिस जो की 21 मई 2026 से शुरू हो रहीं हैं के मद्दे नजर दरगाह पर आने वाले जायरीनों की सहुल्यात के लिए कामों का सिल सिला युद्ध स्तर पर चल रहा है जिसमे खास तौर पर नालों की सफ़ाई और रंगाई पुताई और खेतों की जमीन को टेंटों के लिए एक्सा किया जा रहा है वही लाइट की व्यवस्था के लिए बिल्लियों को लगाने का कार्य जारी है ताकि आने वाले जरीन को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े प्रशासक मौलाना शबाब नक़वी ने बताया हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी ज़ायर को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और बिजली पानी साफ सफाई वगैरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और दरगाह पर इंतजामिया द्वारा तकरीबन सारे एहम कामों को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम किया जा रहा है ताकि आने वाली मजलिसों में बेहतर इंतजाम हो सके और एक खूबसूरत तरीके से इस साल की सालाना मजलिसें मुनाकिद हों सकें दरगाह पर आने वाले ज़ायरीनों की बड़ी तादाद को देखते हुए सीवर लाइन के बड़े पाइप लगवाए जा रहे हैं और नए स्तर पर लैट्रिनों को बनाने का काम जारी है वही बड़े सीवर टैंक के चारों तरफ बाउंड्री कराई जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके मौलाना ने बताया कि आने वाली इन मजलिसों में प्रशासन हमारे साथ पूरी तरीके से कॉर्पोरेट कर रहा है और इंशाल्लाह इन मजलिसों को कामयाब बनाने में प्रशासन का अहम रोल रहेगा

रामपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन, वेतन भुगतान की उठाई मांग

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। उत्तर प्रदेश/ नगर पालिका परिषद रामपुर में कथित भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर एकत्र होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और जल्द समाधान की मांग की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी, कर्मचारियों के शोषण, तथा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर पालिका में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, जिससे परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों को दबाया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारी (ईओ) के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील की। धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नगर पालिका प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

केंद्र एवं प्रदेश के सभी मंत्री/वीआईपी लोग पहले खुद कार पुलिंग कर के पेट्रोल,डीजल बचाए : वेद प्रकाश यादव

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर: मंगलवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एक बैठक शिवसेना के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव के राजपूत कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार आ रहे पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गरीब जनता से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं जबकि खुद प्रधानमंत्री तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकारों के मंत्री तथा वीआईपी लोग बड़ा-बड़ा काफिला लेकर घूमते हैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को अपने साथ-साथ केंद्र एवं प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों विधायकों एवं वीआईपीयो को कार पुलिंग करके, साथ चलने वाले काफिले को छोटा करके जनता को पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश देना चाहिए, वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, वहीं इलेक्शन खत्म होते ही प्रधानमंत्री जी को पश्चिम एशिया के हालात गिरते हुए दिखाई देने लगे उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन था शपथ समारोह था जब तक प्रधानमंत्री जी सब कुछ सामान्य बता रहे थे इलेक्शन के बाद शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल बचाने जैसे बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही इस प्रकार की बातें करेंगे तो जनता तो भ्रमित होगी ही तथा पेट्रोल डीजल को लोग एकत्र करने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइनों में लगे दिखाई देंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं देने चाहिए जिससे जनता भ्रमित हो, बैठक की अध्यक्षता वेद प्रकाश यादव की तथा संचालन विकास यादव नगर अध्यक्ष द्वारा किया गया, बैठक में मुख्य रूप से वेद प्रकाश यादव, विकास यादव, रवि यादव, मोनू यादव, निकुंज शर्मा, मोहित कपिल, दिनेश, राजकुमार, अर्जुन, राजेंद्र यादव, मयंक आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

साहनपुर में विकास कार्यों की एक और बड़ी उपलब्धि

» अब डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे साहनपुर के छात्र

» खुर्शीद मंसूरी जनता ने मौका दिया तो नजीबाबाद ने भी विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

साहनपुर : साहनपुर में आधुनिक शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम डिजिटल लाइब्रेरी" का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम नजीबाबाद आशुतोष जायसवाल, साहनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी एवं समाजसेवी डॉ. राखी आनंद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसडीएम नजीबाबाद आशुतोष जायसवाल ने नगर पंचायत साहनपुर द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी से क्षेत्र के छात्रों को आधुनिक शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित अध्ययन की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे युवाओं का भविष्य और अधिक मजबूत होगा। साहनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि नगर पंचायत साहनपुर लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जीजीआईसी कॉलेज की सौगात देकर क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा नगर में तिरंगा फ्लैग स्थापना, गार्डन निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, 125 से अधिक सड़कों का निर्माण, डिजिटल वेलकम बोर्ड, फ्रीजर स्थापना, कूड़ा निस्तारण केंद्र निर्माण, सफाई व्यवस्था के लिए नई गाड़ियों की खरीद एवं मैनुअल लाइब्रेरी जैसी कई विकास योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति मिलने पर आगे भी नई विकास योजनाओं को लागू कराया जाएगा। समाजसेवी डॉ. राखी आनंद अग्रवाल ने डिजिटल लाइब्रेरी की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा एवं आधुनिक तकनीक से जुड़ी पढ़ाई में काफी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. इस्लाम ने की। इस अवसर पर राहतपुर प्रधान मुस्तफा, मंडावली के पूर्व प्रधान वाजिद मकरानी, साबू मकरानी, अलीपुर प्रधान आसिफ, पूर्व प्रधान नफीस अहमद, भूरे प्रधान, फ़िरासत हुसैन, डॉ. इस्लाम, अशोक कुमार, प्रशांत महासागर, ललित कुमार, नगर पंचायत साहनपुर के सभासदगण, शद्दन खान, इक़बाल अहमद, फुरकान अहमद, वकार अहमद, दीपक, मुजफ्फर हुसैन, आबिद, चांद, मौलाना सलीम, मास्टर शाहनवाज़, इरशाद, भागूवाला के पूर्व प्रधान अब्दुल हई, शमशीद, रिज़वान खान, नईम अहमद, डॉ. नसीम, शाहबाज खान, मास्टर फराहीम, असलम अंसारी, नौशाद सरवरी, नदीम सलमानी, जाफर, कफील अंसारी "छोटे उस्ताद", सय्यद इरशाद, वीरेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

तड़के लगी भीषण आग से दहला नजीबाबाद का चौक बाजार कटहरा मार्केट, घंटों मशक्कत करती रही फायर ब्रिगेड

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

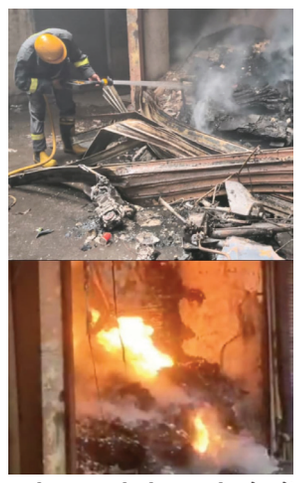

नजीबाबाद। नगर के कटहरा मार्केट में सोमवार तड़के तीन मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत उसकी चपेट में आ गई और आसपास का क्षेत्र धुएं के गुबार से भर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे स्थानीय लोगों ने मार्केट से धुआं उठता देखा। इसके बाद तत्काल दुकान मालिक और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग लगातार विकराल रूप धारण करती रही। सुबह करीब 9 .30 बजे तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे। आग की तेज लपटों और धुएं के कारण बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे में दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दुकान में रखा लाखों रुपये का कपड़ा एवं अन्य सामान जल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और दमकल विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

रामपुर पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान ऑनलाइन मीटिंग में थाना प्रभारी रहे नदारद, अनुशासन पर उठे सवाल

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक ऑनलाइन बीसी मीटिंग आयोजित की गई, लेकिन इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कई थाना प्रभारी नदारत दिखाई दिए। मीटिंग में थाना प्रभारियों की गैरमौजूदगी को लेकर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जनसुनवाई के समय पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा कार्यालय में मौजूद थे और फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान ऑनलाइन बीसी मीटिंग के माध्यम से थाना प्रभारियों को निर्देश देने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई थानों के प्रभारी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे यह स्पष्ट नजर आया कि संबंधित अधिकारियों में अनुशासन की कमी है और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों और मौजूद फरियादियों का कहना है कि यदि ऑनलाइन मीटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में थाना प्रभारी ही उपस्थित नहीं रहते, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस घटना से ऐसा प्रतीत हुआ मानो थाना प्रभारियों को पुलिस कप्तान का कोई भय या दबाव नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस मामले को गंभीरता से लिया जा सकता है और गैरहाजिर थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल यह घटना पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा इस लापरवाही पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।

संभल को प्रदेश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा विकास कार्य : चौधरी मुशीर अली खान

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल: नगर पालिका परिषद की चेयरमैन आसिया मुशीर अली खान, अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी एवं चेयरमैन पति तथा एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता चौधरी मुशीर अली खान के नेतृत्व में नगर में विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य युद्धस्तर पर कराए जा रहे हैं। नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए दिन-रात कार्य जारी है, जिससे संभल की तस्वीर लगातार बदलती नजर आ रही है। चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान ने कहा कि नगर पालिका परिषद की प्राथमिकता संभल को विकास और साफ-सफाई के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर-1 स्थान पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से संभल आए तो उसे एक सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित शहर दिखाई दे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट, भव्य सौंदर्यीकरण कार्य तथा विभिन्न स्थानों पर विशेष सजावट कराई जा रही है, जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक नगर में एक हजार से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है तथा आने वाले समय में जो भी विकास कार्य शेष हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। साथ ही संभल की ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करने के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिल सके। अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी ने बताया कि नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, शहर के प्रवेश मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार तथा अन्य कई महत्वपूर्ण विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद का उद्देश्य संभल को एक आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक शहर के रूप में विकसित करना है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके।

बरेली में आंधी-बारिश के बाद बड़ा खतरा टला: चौकी चौराहे पर झुका विशाल गंतव्य बोर्ड हटाया गया, नगर निगम अलर्ट मोड में

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा): मंगलवार को बरेली में आई तेज आंधी और बारिश के बाद शहर के व्यस्त चौकी चौराहे पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। चौराहे पर लगा विशाल गंतव्य संकेत बोर्ड तेज हवाओं के दबाव में अचानक एक ओर झुक गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोर्ड को हटवा दिया और संभावित दुर्घटना को टाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही मौसम खराब था और तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी थी। इसी दौरान चौकी चौराहे पर लगा भारी-भरकम लोहे का संकेत बोर्ड असंतुलित होकर झुकने लगा। देखते ही देखते आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चौराहे से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए और कई राहगीर सुरक्षित दूरी पर चले गए। लोगों को डर था कि यदि बोर्ड अचानक गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र शहर के सबसे व्यस्त यातायात मार्गों में शामिल है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि कुछ समय तक लोग दहशत में रहे। कई लोगों ने नगर निगम और पुलिस को फोन कर तत्काल सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और हालात का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पाया कि तेज हवा और लगातार बारिश के कारण बोर्ड का बेस कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद नगर निगम कर्मियों ने मशीनों और तकनीकी उपकरणों की मदद से संकेत बोर्ड को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा के लिहाज से कुछ समय के लिए चौराहे पर यातायात आंशिक रूप से रोका गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखा। नगर निगम अधिकारी सच्चिदानंद ने बताया कि मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण संकेत बोर्ड का ढांचा कमजोर हो गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए एहतियातन बोर्ड को हटाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम द्वारा अब शहर के प्रमुख चौराहों, बड़े होर्डिंग्स और गंतव्य संकेत बोर्डों का विशेष निरीक्षण कराया जा रहा है। जहां भी जर्जर या खतरनाक स्थिति मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। लोगों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर पुराने और जर्जर होर्डिंग्स तथा संकेत बोर्ड लगे हुए हैं, जो खराब मौसम के दौरान खतरा बन सकते हैं। नागरिकों ने मांग की कि नगर निगम नियमित रूप से ऐसे ढांचों की जांच कराए और समय रहते मरम्मत या हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना ने शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और जर्जर ढांचों की निगरानी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नवनिर्वाचित असम सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा व मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को दी बधाई

लोकतंत्र की शान

गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को असम पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नवनिर्वाचित राजग सरकार के शपथ ग्रहण में शिरकत की। हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थानीय कलाकारों ने वाद्ययंत्रों व नृत्य के साथ परंपरागत ढंग से स्वागत किया, जबकि पारंपरिक परिधान में उपस्थित महिलाओं ने उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर मौजूद जन समुदाय ने सीएम योगी का जयकारों संग स्वागत किया तो सीएम योगी ने भी हाथ जोड़कर सभी के प्रति आभार जताया।

इस बार बनेगी सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार : राजेंद्र खड़कवंशी

लोकतंत्र की शान

हसनपुर: मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हसनपुर 42 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चमरपतैइ में pda पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़कवंशी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का आह्वान किया तथा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनकल्याण योजनाओं का विस्तार पूर्वक सभी ग्राम वासियों को जानकारी दी, इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक टिंकू नागर, सुरेंद्र सिंह,विपिन नागर, बलवीर सिंह, सुधीर, अरविंद, अमर सिंह ,कोशिंदर सिंह, प्रदीप, राहुल, भाकर,अंकित, राजकुमार प्रधान, प्रमोद नागर, वरुण नागर, प्रेमपाल, इंद्रपाल, शमीम अहमद, कलुआ नागर, पप्पन नागर, बाबूराम, उवैस चौधरी, सुहैल चौधरी, राजवीर, फुर्ती, लोकेश , प्रदीप कुमार शर्मा, कैलाश नागर, नरेंद्र नागर, अमित खारी आदि सहित भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे ।

"ब्लिंकिट के गोदाम का नजीबाबाद में विरोध तेज, छोटे व्यापारियों ने जताई रोज़गार खत्म होने की आशंका"

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद : नजीबाबाद में जल्द खुलने जा रहे ब्लिंकिट कंपनी के गोदाम को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ती जा रही है। सोमवार रात्रि करीब 8:30 बजे माहेश्वरी धर्मशाला नजीबाबाद में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नगर इकाई की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। बैठक में नजीबाबाद डिस्ट्रीब्यूटर संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि नजीबाबाद जैसे छोटे नगर में यदि ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनी अपना गोदाम खोलकर डोर-टू-डोर होम डिलीवरी शुरू करती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को होगा। व्यापारियों का कहना था कि पहले से ही रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के शोरूम खुलने से स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ है और अब ब्लिंकिट जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के आने से छोटे दुकानदारों के सामने रोज़गार बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा। संगठन के वरिष्ठ प्रदेश मंत्री संजीव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी कंपनियों को केवल महानगरों तक सीमित रखा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे शहरों में इनके आने से स्थानीय व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक छोटा व्यापारी अपनी पूंजी लगाकर व्यापार करता है, कर्मचारियों को रोजगार देता है और सरकार को जीएसटी के रूप में टैक्स भी देता है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण अब वही व्यापारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले चरण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे चरण में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में मुकेश जिंदल, अर्पित मेहरा, कमल बंधु, अनुज अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, जोगराम भुजिया वाले, मोहम्मद अलाउद्दीन सरदार, हरिंदर सिंह, भाजपा नेता लवी अग्रवाल, अंकुर एजेंसी, नीरज सिंघल, शक्ति गर्ग सहित कई व्यापारियों ने अपने विचार रखे।

संक्षिप्त समाचार

शादी समारोह में तोड़फोड़, पिता की मौत, पुलिस पर एक्शन नहीं लेने और दबाव बनाने का आरोप, जांच जारी

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के जावज गांव में 2 दिन पहले पिता ने बेटी का कन्यादान किया था। वहीं 2 दिन बाद पिता का शव घर से मिला है। मृतक कि पहचान वैशाली के महनार के जावज गांव के अशोक महतो (50) के रूप में हुआ है। बताया गया कि शादी समारोह में दबंगों ने तोड़फोड़ की थी और फिर पिता की संदिग्ध मौत हुई है।

पिता दबंग का पैर हाथ पकड़ते रहे लेकिन दबंगों ने तोड़फोड़ करना नहीं रोका। आरोप है कि शादी समारोह में पहुंचे कुछ मनचलों और दबंगों ने पहले बारातियों के साथ मारपीट कि घटना को अंजाम दिया जिसके बाद बारात की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, शादी के लिए बना खाना फेंक दिया गया। इसके साथ ही चूल्हा भी तोड़ दिया गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के दौरान महनार पुलिस और 112 नंबर पर लगातार फोन किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची भी लेकिन परिजनों के अनुसार तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पहले शादी कर लीजिए कहकर मामला को शांत कराने की कोशिश हुई। यहीं से अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उसी रात मारपीट, तोड़फोड़, खाना फेंकने, चूल्हा तोड़ने और घायलों के बयान के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाती तो अगर आरोपियों को उसी समय हिरासत में लिया जाता तो शायद आज एक बेटी के सिर से उसके पिता का साया नहीं उठता।

अंचल अमीन 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, हाजीपुर में जमीन मापी-परिमार्जन के लिए मांगे थे 3 लाख

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) ने सोमवार को लालगंज अंचल कार्यालय में तैनात अंचल अमीन सुजीत कुमार को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अमीन पर जमीन के परिमार्जन और मापी के काम के बदले लाखों रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने बताया कि सराय थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी सराय निवासी आनंद कुमार और लालगंज थाना क्षेत्र के मुर्गीयाचक निवासी पप्पू कुमार ने पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों ने जमीन के परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके निष्पादन के लिए अमीन सुजीत कुमार रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत के अनुसार, पप्पू कुमार की छह हिस्से वाली जमीन की मापी और परिमार्जन के लिए तीन लाख रुपए मांगे गए थे, जबकि आनंद कुमार से 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पीड़ितों ने निगरानी इकाई से संपर्क किया। विशेष निगरानी इकाई ने शिकायत मिलने के बाद मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच में पुष्टि हुई कि अंचल अमीन सुजीत कुमार वास्तव में रिश्वत की मांग कर रहे थे। सत्यापन रिपोर्ट सही पाए जाने के बाद एसवीयू थाना में कांड संख्या-18/2026, 11 मई 2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उपाधीक्षक चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। योजना के तहत पप्पू कुमार को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही सुजीत कुमार ने रुपए स्वीकार किए, पहले से तैनात निगरानी टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

व्यक्ति से 1 लाख रुपये की ठगी, बदमाशों ने बातों में उलझाकर झोले से निकाले पैसे,साइकिल से घर लौट रहे थे

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। लालगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने नुनु बाबू चौक के समीप एक व्यक्ति को बातों में उलझाकर उसके झोले से एक लाख रुपये निकाल लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, शाहपुर कासिम निवासी दुखा सिंह सोमवार को लालगंज स्थित स्टेट बैंक से एक लाख दस हजार रुपये निकालकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। वे जैसे ही कमर्स कॉलेज नहर के पास पहुंचे, वहां पहले से खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुखा सिंह से किसी डॉक्टर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इसी दौरान दो अन्य युवक बाइक से वहां पहुंचे और बातचीत में शामिल हो गए। बातों में उलझाकर बदमाशों ने दुखा सिंह का ध्यान भटका दिया। जब तक दुखा सिंह कुछ समझ पाते, उनके झोले से एक लाख रुपये निकाल लिए गए। बदमाशों ने झोले में केवल दस हजार रुपये छोड़कर बाकी पैसे लेकर बाजार की ओर फरार हो गए। घर पहुंचने पर जब दुखा सिंह ने अपना झोला देखा, तो उन्हें ठगी का पता चला। झोले में केवल दस हजार रुपये ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र किशन के साथ घटनास्थल पहुंचकर लालगंज थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस मामले की जांच कर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

पद्मश्री कृषि वैज्ञानिक डॉ. गोपालजी त्रिवेदी का निधन, पटना में ली अंतिम सांस

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और पूर्व कुलपति डॉ. गोपालजी त्रिवेदी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने पटना के मेदांता अस्पताल में सुबह करीब 5:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके पुत्र डॉ. रमन त्रिवेदी ने बताया कि रविवार को सांस संबंधी परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उनका निधन हो गया। गायघाट प्रखंड स्थित मतलुपुर गांव निवासी डॉ. त्रिवेदी कृषि क्षेत्र में अपने नवाचारों और किसानों की आय बढ़ाने वाले मॉडल के लिए देशभर में जाने जाते थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। डॉ. गोपालजी त्रिवेदी ने विशेष रूप से मुजफ्फरपुर की पहचान मानी जाने वाली लीची के पुराने बागों को बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 'पुनर्जीवन कैनोपी मैनेजमेंट' तकनीक विकसित की थी। वर्ष 2003 में शुरू की गई इस तकनीक के तहत 40-50 साल पुराने और अनुत्पादक लीची पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई-छंटाई कर उन्हें फिर से फलदार बनाया जाता था। पेड़ों की ऊंचाई कम कर नई शाखाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाता था, जिससे पुराने बागों को हटाए बिना ही नए पेड़ों जैसी उपज मिलने लगी। प्रारंभिक प्रयोग में ही उनके बाग के 10 पेड़ों से सवा क्विंटल तक अतिरिक्त उत्पादन हुआ था। मुजफ्फरपुर में करीब 12 हजार हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। ऐसे में उनकी तकनीक ने हजारों किसानों को पुराने बागों के संरक्षण और बेहतर उत्पादन का रास्ता दिखाया। डॉ. त्रिवेदी ने जलजमाव वाले क्षेत्रों में खेती को नई दिशा देने का भी काम किया। उन्होंने मखाना, सिंघाड़ा और मत्स्य आधारित समेकित खेती को बढ़ावा देकर परती और जलजमाव वाली जमीन को उपयोगी बनाया। उनके प्रयास से 22 किसानों ने 86 एकड़ भूमि को मत्स्य आधारित खेती मॉडल में विकसित किया। इस मॉडल में मछली पालन, पौधारोपण और अन्य फसलों की खेती एक साथ की जाती थी। इसे 'बाबा परियोजना' यानी बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर परियोजना के नाम से पहचान मिली। इससे भूजल स्तर में सुधार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (पूर्व में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय) के पूर्व कुलपति भी रहे। कृषि विस्तार, तकनीकी आधारित खेती, किसानों की आय दोगुनी करने और सतत कृषि मॉडल पर उनका कार्य बेहद प्रभावशाली माना जाता है।

बांका-बेगूसराय समेत 4 जिलों में तेज बारिश, 19 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट

लोकतंत्र की शान, पटना

अगले 7 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम

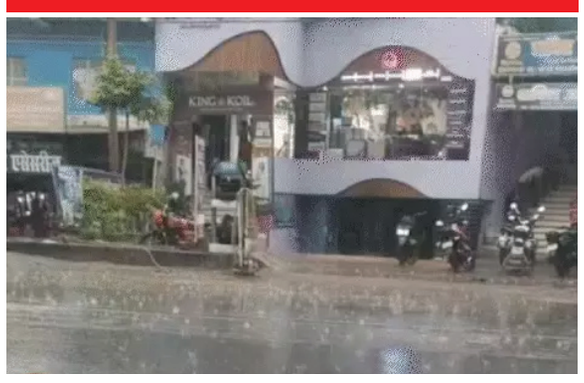

बिहार के कई जिलों का मौसम मंगलवार को फिर से बदल गया। दोपहर के बाद शाम में बांका, लखीसराय और बेगूसराय में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। जहानाबाद में बूंदाबांदी शुरू है। सुबह सुपौल में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बांका, जमुई और पटना में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि खगड़िया, दरभंगा, बेगुसराय, समस्तीपुर एवं सहरसा में आंधी-बारिश की ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में 40 से 60Kmph की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई है। साथ ही अकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अब तक सामान्य से 193% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कैमूर 40 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा।

पटना में आज तेज बारिश की संभावना: पटना में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मंगलवार को राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही तेज बारिश के साथ-साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। दिन के समय उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आने से राहत मिलने की उम्मीद है।

पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1 से 2 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहने से सुबह और रात में हल्की राहत महसूस हुई। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई है। इसके बाद आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

सहरसा में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति सुचारु, जिला प्रशासन ने जारी की स्थिति रिपोर्ट

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा जिले में घरेलू एलपीजी (LPG) गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आम लोगों को आश्वस्त किया है कि जिले में 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु रूप से जारी है। प्रशासन द्वारा इंडेन, भारत गैस एवं एचपी गैस कंपनियों के वितरकों के साथ प्रतिदिन स्टॉक एवं वितरण की समीक्षा की जा रही है। जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिले में कुल 10,531 गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि प्रतिदिन औसतन 5,395 सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। वहीं कुल लंबित बुकिंग (बैकलॉग) की संख्या 20,431 बताई गई है। जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडेन गैस के पास 3,980 सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है तथा प्रतिदिन औसतन 2,328 सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। एचपी गैस के पास 4,564 सिलेंडरों का स्टॉक एवं 2,191 सिलेंडरों का दैनिक वितरण हो रहा है, जबकि भारत गैस के पास 1,987 सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है और प्रतिदिन 876 सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। प्रेस विज्ञप्ति में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कुछ वितरकों के पास बुकिंग की संख्या अधिक होने के बावजूद रिफिल की आपूर्ति लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में जिले भर में कुल 5,395 गैस सिलेंडरों की सफल डिलीवरी की गई है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें तथा गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण करने से बचें। जिला प्रशासन ने सभी गैस वितरकों को बुकिंग क्रम के अनुसार ही होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई वितरक कालाबाजारी करता है अथवा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकते हैं। आपूर्ति निरीक्षकों को सभी गोदामों का औचक निरीक्षण करने तथा होम डिलीवरी व्यवस्था पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

बिहटा में 9 लोगों पर मर्डर की एफआईआर, 3 की हो चुकी गिरफ्तारी

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के बिहटा में शिव साव (64) की हत्या हुई थी। मामले में उनकी पत्नी कलावती देवी ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिगाय है, बाकी को पुलिस तलाश रही है। कलावती देवी ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम को पाटीदारों पति और परिवार के साथ शराब के नशे में बिना किसी वजह के मारपीट की थी। इस घटना में परिवार के सदस्य घायल भी हुए थे, जिसके बाद रात में मामला शांत हो गया था। सोमवार की सुबह जब शिव साव घर पर नहीं मिले, पता चला कि वे सुबह करीब 4 बजे टहलने और चाय पीने के लिए बाहर निकले थे। सुबह 7 बजे के आसपास गांव वालों ने सूचना दी कि उनका शव घर के पीछे खेत में एक नींबू के पेड़ से लटका हुआ है। घटना कटेसर गांव की है। कलावती देवी ने आशंका जताई है कि उनके पति को उन्हीं लोगों ने पहले पीटा और फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्हें पेड़ से लटका दिया। आए दिन आरोपी गाली-गलौज और मारपीट करते थे। हमलोग मजदूर वर्ग के हैं और कमजोर हैं। जिसके कारण हमें दबाकर रखा जा रहा था। इसी वजह से मारपीट भी होती थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आसपास के गांवों और क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है ताकि फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। थानाप्रभारी अमित कुमार ने बताया कि अधेड़ व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या मामले में मृतक की पत्नी कलावती देवी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। जिसमें से पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तार की है, जबकि अन्य फरार हैं।

मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षा को लेकर संचालन समिति की बैठक आयोजित

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय वेश्म, सहरसा में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दीपेश कुमार ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, एलडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, जिला प्रबंधक डीआरसीसी, जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम तथा बिहार शिक्षा परियोजना के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में महिला एवं बाल विकास निगम, सहरसा के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, गतिविधियों एवं बैठक की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी को दी गई। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन, त्वरित सेवा उपलब्धता एवं महिलाओं से जुड़े मामलों के प्रभावी निष्पादन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

सहयोग शिविर की तैयारियों की समीक्षा, लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: स्थानीय विकास भवन में मंगलवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 19 मई 2026 को प्रखंडवार चिन्हित स्थलों पर आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सहयोग शिविर हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, उनके निष्पादन की वर्तमान स्थिति, लंबित न्यायिक वादों के निपटारे के लिए की गई कार्रवाई तथा विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों — तकनीकी विभाग, मनरेगा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, आपूर्ति एवं अन्य विभागों — को निर्देश देते हुए कहा कि सहयोग शिविर से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार अंतिम निष्पादन शिविर आयोजन तिथि से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को नल-जल योजना के निर्बाध एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया। लघु सिंचाई विभाग को पंचायती राज कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर बंद पड़े राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों एवं कार्यालयों को लंबित न्यायिक वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता निशांत, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) संजीव कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता (वि० जांच) गणेश कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

सदाकत आश्रम में कांग्रेस की बैठक राजेश राम-कृष्णा अल्लावरु मौजूद

लोकतंत्र की शान, पटना

बिहार कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हो रही। इसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम कर रहे। संगठन सृजन साथी अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, पर्यवेक्षकों, कनेक्ट सेंटर से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। संगठन सृजन साथी अभियान को लेकर बिहार कांग्रेस ने 53 सांगठनिक जिलों में 155 जिला ऑब्जर्वर को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के निर्देश पर हुई है। इस सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया है जिनके ऊपर संगठन सृजन साथी अभियान के सफलता की जिम्मेदारी रहेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी को जिला और बूथ स्तर पर मजबूत करना है।

बिहार कांग्रेस ने पिछले महीने संगठन सृजन साथी अभियान के लिए डिजिटल ड्राइव की शुरुआत की थी। इससे जुड़ने के लिए लोग BPCC ऐप पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आवेदक किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जिला अध्यक्ष को 2,000 सृजन साथी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए कम से कम 200 सृजन साथी बनाना अनिवार्य किया गया है।

दवा की थोक-खुदरा दुकानें 20 मई को बंद रहेंगी

लोकतंत्र की शान, पटना

ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और केंद्र सरकार की नई दवा नीति के विरोध में देशभर के दवा कारोबारियों ने 20 मई को एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान बिहार सहित पूरे देश में थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवा कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते दायरे से पारंपरिक मेडिकल स्टोरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया है। संगठनों ने सभी दवा विक्रेताओं, फार्मासिस्टों और थोक व्यापारियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आंदोलन के तहत 16 से 19 मई तक दवा दुकानदार काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। हड़ताल 19 मई की देर रात से प्रभावी हो जाएगी। पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन कुमार यादव ने कहा कि यह आंदोलन केवल कारोबार बचाने के लिए नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और दवा वितरण व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है। बिना डॉक्टर के उचित सलाह के दवाओं की आपूर्ति कर दी जाती है। दवा विक्रेताओं ने विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, नशीली दवाओं और शेड्यूल एच-एच1 श्रेणी की दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीके सिंह और महासचिव राजेश आर्या ने बताया कि हजारों छोटे दुकानदारों और फार्मासिस्टों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

बांकीपुर बस स्टैंड को तोड़कर बनेगा 5 स्टार होटल

लोकतंत्र की शान, पटना

- **28 हजार यात्रियों को बस के लिए दूसरी जगह जाना होगा, इसी महीने जमीन होगी खाली**

पटना का बांकीपुर बस स्टैंड अब इतिहास बनने जा रहा है। यात्रियों की भीड़ और बसों की आवाजाही से गुलजार रहने वाला यह परिसर अब एक नई कहानी लिखने जा रहा है। गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास स्थित 67 साल पुराने इस बस डिपो को तोड़कर एक फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। एक महीने के अंदर इस परिसर को खाली करने की तैयारी है।

बांकीपुर बस स्टैंड का इतिहास: पटना का बांकीपुर बस स्टैंड बिहार के परिवहन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह डिपो दशकों तक पटना की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ रहा है। इसकी शुरुआत साल 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की स्थापना के साथ हुई थी। यह डिपो दशकों तक पटना, आसपास के जिलों और विशेष रूप से लंबी दूरी की बसों के लिए प्रमुख केंद्र बना रहा। बस स्टैंड लगभग 3.5 एकड़ में फैला है।

जेपी गंगा पथ के किनारे बनेगा नया बस स्टैंड: ऐसी चर्चा है कि बांकीपुर बस स्टैंड शिफ्ट करने के लिए जेपी गंगा पथ किनारे 5 एकड़ में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। गंगा नदी के किनारे वाली सड़क के उत्तर में जगह चुना गया है। पिछले दिनों जमीन की नापी कर सीमांकन किया गया। BSRTC ने नए बस स्टैंड के लिए भूमि के औपचारिक आवंटन की मांग करते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। जब तक आधिकारिक रूप से जमीन का आवंटन नहीं हो जाता तब तक बस संचालन का प्रबंधन कई स्थानों से किया जाएगा।

सिटी बसों का परिचालन मल्टी मॉडल हब से किया जाएगा: फिलहाल सिटी बसों का परिचालन मल्टी मॉडल हब और फुलवारीशरीफ स्थित डिपो से किया जाएगा। वहीं, बैरिया स्थित ISBT से अभी प्राइवेट बसों का परिचालन हो रहा है। वहां से भी कुछ जिलों की सरकारी बसों का परिचालन होना है। कुछ बसों को पहले से ही गंगा पथ के पास खड़ा किया जा रहा है और परिचालन समय के दौरान उन्हें कारगिल चौक पर लाया जा रहा है।

बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर लग्जरी ताज होटल बनेगा। इसके लिए मार्च महीने में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSTDCL) और सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड के बीच MoU साइन हुआ था। यह समझौता सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हुआ है। इस समझौते के मुताबिक द इंडियन होटल समूह द्वारा फाइव स्टार ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। होटल निर्माण के लिए DPR तैयार हो गया है। 3D इमेज बनाई गई है। बस स्टैंड खाली होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद फाइनल पोजिशनिंग की जाएगी। किसी भी तरह के बदलाव होने पर फिर से स्ट्रक्टरिंग की जाएगी। एक बार जगह खाली होने के बाद, पटना नगर निगम से NOC के लिए अप्लाई किया जाएगा। फिर काम शुरू होगा।

संक्षिप्त समाचार

गाड़ी संख्या 11753,54 रीवा-इतवारी-रीवा का ठहराव स्लीमनाबाद रेलवे स्टेशन पर

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, कटनी सभी क्षेत्रवासियों व सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ व सहृदय धन्यवाद जिन्होंने एकजुट होकर सफलतापूर्वक स्लीमनाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों के ठहराव हेतु आंदोलन संघर्ष किया |गाड़ी संख्या 11753,54 रीवा-इतवारी-रीवा का ठहराव स्लीमनाबाद रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित | दिनाँक 16/05/2026 #स्लीमनाबाद स्टेशन पर सायं 19:50 बजे गाड़ी संख्या 11754 रीवा -नेता जी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जंक्शन का ठहराव सुनिश्चित हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में स्वागत समारोह कर्यक्रम रखा गया है |निवेदक<ग्राम विकास संघर्ष समिति स्लीमनाबाद

हसनपुर केमिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल 20 मई को, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः मंगलवार को हसनपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओ की बिक्री (ई फार्मेसी) और बड़े कॉर्पोरेट घरानो की "प्रिडेटरी प्राइसिंग, नीतियों के विरोध में 20 मई 2026 को हसनपुर सहित देशभर की दवा दुकान बंद रखने को लेकर एसडीम को ज्ञापन दिया हसनपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस के आह्वान पर की जा रही है, वही अध्यक्ष संदीप अग्रवाल एवं महामंत्री अरविंद गुप्ता ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी मांगों और चिंताओं से अवगत कराया संगठन ने सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगे रखी हैं जिसमें अवैध फार्मेसी पर रोक लगाते हुए वर्ष 2018 की अधिसूचना सजीएसआर 817 ई को तत्काल वापस लेना शामिल है, दूसरी मांग कोविड-19 काल के दौरान लागू की गई अधिसूचना सजीएसआर 220 ई को समाप्त करना है क्योंकि संगठन का आरोप है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तीसरी मांग बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा बाजार बिगड़ने के उद्देश्य से दी जा रही भारी छूट यानी प्रिडेटट्री प्राइसिंग पर रोक लगाना है, केमिस्ट एसोसिएशन का तर्क है की दवा कोई साधारण वस्तु नहीं है ऑनलाइन बिक्री और कॉर्पोरेट दखल से देश के 12.40 लाख केमिस्टों की आजीवीका संकट में है संगठन ने जन स्वास्थ्य पर मंडराते खतरों को भी रेखांकित किया है, इसमें बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा की अवैध बिक्री, नशीली और प्रतिबंधित दबाव की आसान उपलब्धता, नकली दवा का प्रसार असुरक्षित भंडारण की समस्या और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर का बढ़ता जोखिम शामिल है, अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि बार-बार निवेदन के बावजूद सरकार छोटे दुकानदारों की अनदेखी कर रही है उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो देशभर की दवा विक्रेता से जुड़े लगभग 5 करोड लोगों का भविष्य प्रभावित होगा, संगठन ने सरकार से निष्पक्ष व्यापार प्रणाली और स्थानीय केमिस्टों के संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाने का आग्रह किया है ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से संदीप अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, सुधीर कुमार चौहान, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद नासिर, राजीव अग्रवाल, खुशी मोहम्मद, अलीमुद्दीन, जुनैद, मनोज कुमार आदि सहित दर्जनों मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे।

कस्बा उझारी में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में FCC क्रिकेट क्लब ने जीता मैच

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर/ उझारीः तहसील क्षेत्र के कस्बा उझारी में सोमवार को एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें एफसीसी क्रिकेट क्लब और डॉन क्रिकेट क्लब के बीच 16/16 ओवरो का यह मैच खेला गया,

जिसमें डॉन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में एफसीसी क्रिकेट क्लब के कप्तान शोएब रैना की शानदार पारी की बदौलत टीम ने 190 रन बनाकर जीत हासिल की, क्रिकेट मैच का आयोजन उझारी में वन के पीछे दंगल ग्राउंड पर कराया गया, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चौधरी फहीमुद्दीन ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए विजेता टीम एफसीसी क्रिकेट क्लब को 20000 रूपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की, वही उपविजेता टीम डॉन क्रिकेट क्लब को 10000 रुपए नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि चौधरी फहीमुद्दीन ने युवाओं के खेल के महत्व और इसके माध्यम से भविष्य बनाने के अवसर के बारे में प्रेरित किया, वहीं पूरे क्रिकेट की कमेंट्री सुहेल चौधरी ने बहुत ही शानदार तरीके से की, इस मौके पर सुहेब चौधरी, इशाक उर्फ छोटे सेक्रेटरी, आफताब आदि सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

संगठन के तोड़ने वालों से रहे सावधान

लोकतंत्र की शान , राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

सोनीपतः को हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 असली जिला कमेटी सोनीपत जिसके प्रदेश अध्यक्ष आर.के.नागर हैं, हमारे जिला कमेटी का चुनाव 27 अप्रैल को पहले ही हो चुका है। परंतु आज कुछ बागी और चंदा चोर विश्वास घाती लोगों ने आज एक आम भंडारे का नाम देकर बाहरी लोगों को इकट्ठा करके तथा अन्य कई यूनियन के कर्मचारी और नेताओं को बुलाकर भीड़ दिखाकर फर्जी जिला कमेटी चुनाव हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन 1266 के नाम पर किया है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के नियमों और यूनियन के नियमों के विरुद्ध है। और गैरकानूनी है। हम पहले से जिला कमेटी के पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह जिला प्रधान, राकेश त्यागी-जिला चेयरमैन, योग प्रकाश नागर जिला सचिव, जोगिंदर सिंह जिला उपाध्यक्ष, अरुण कुमार, शमशेर सिंह उपाध्यक्ष, राकेश चावरिया प्रचार सचिव, बंसीलाल प्रचार सचिव, समेश कुमार सलाहकार, समे सिंह ऑडिटर, सुरेश रोहिल्ला राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला सलाहकार, विजेंद्र रिवाल राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला सलाहकार, ध्रुव कुमार जिला राज्य प्रैस सचिव, आज की फर्जी यूनियन व फर्जी चुने गए पदाधिकारी का खंडन करते हैं। हमारी यूनियन हुड्डा जनस्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 इनका कोई मानयता नहीं देती। आज जिस फर्जी राज्य प्रधान ने चुनाव कराया है वह खुद बोगस है। नकली है। और इस प्रकार हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 की जिला कमेटी खोलना इनका कोई हक अधिकार नहीं है। इस चुनाव के खिलाफ हम लेबर कोर्ट में तथा एचएसवीपी के अधिकारियों के सामने जांच करने की मांग करेंगे कि इन से इस यूनियन रजिस्ट्रेशन की ओरिजिनल कॉपी देखी जाए। आज का प्रैस नोट एचएसवीपी के सभी उच्च अधिकारियों को और माननीय लेबर कमिश्नर कम रजिस्टर लेबर डिपार्मेंट हरियाणा चंडीगढ़ को भी सादर प्रेषित किया

सेवानिवृत्त शिक्षक ने लिपिक पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप

कलेक्टर को पत्र लिखकर उठाई कार्यवाही की मांग

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा चतुर्थ क्रमोन्नति आदेश जारी करने के नाम पर मांगी जा रही रिश्वत की फरियाद कलेक्टर के यहां आवेदन देकर की है। तत्संबंध में सेवानिवृत्त शिक्षक भागवत प्रसाद मिश्रा ने 23 अप्रैल 2026 को दिए आवेदन में कहा है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमबाबा से वह 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के पत्र क्रमांक/2548, दिनांक 2 अप्रैल 2026 द्वारा समस्त प्राचार्यों को लेख किया यगा था कि ऐसे शिक्षकों को 35 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान प्रदाय हेतु प्रस्ताव तथा 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाए। संदर्भित पत्र के परिपाल में संकुल प्राचार्य बरमबाबा द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक भागवत प्रसाद मिश्रा को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव तथा 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली के साथ समस्त अभिलेख संलग्न कर दिनांक 9 अप्रैल 2026 को स्थापना प्रभारी लिपिक अनितेश सिंह परिहार से परीक्षण कराकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के आवक शाखा में जमा किया गया था। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत कराने के लिए प्रभारी स्थापना 3 लिपिक द्वारा 5 हजार की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत देने से इंकार करने पर सेवानिवृत्त शिक्षक भागवत प्रसाद मिश्रा का नाम सम्मिलित नहीं किया गया। भागवत प्रसाद मिश्र ने लिपिक की मनमानी एवं खुलेआम रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कलेक्टर विकास मिश्रा से करते हुए कार्यवाही की मांग उठाई है।

पवई थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार 'के.एफ. रुस्तमजी' पुरस्कार से सम्मानित

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पन्ना जिले के पवई थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोमवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह यादव और पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

विशिष्ट श्रेणी में मिला सम्मानः निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार को यह पुरस्कार वर्ष 2019-20 और 2021-22 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिए गए विशेष योगदान के लिए दिया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुल 101 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों (परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट) में सम्मानित किया।

सम्मान पाकर जताया आभारः पुरस्कार ग्रहण करने के बाद निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार ने इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए गौरव की बात है और इससे उन्हें भविष्य में और भी अधिक ऊर्जा एवं निष्ठा के साथ जनसेवा और सुरक्षा के दायित्वों को निभाने की प्रेरणा मिलेगी।

पवई क्षेत्र सहित पन्ना जिले में खुशी की लहरः थाना प्रभारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलने की खबर मिलते ही पवई और पन्ना जिले के पुलिस विभाग सहित स्थानीय नागरिकों में हर्ष का माहौल है। वरिष्ठ अधिकारियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

23 मई को लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बघेलखंड ट्रस्ट ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। राजधानी के बघेलखंड भवन में आगामी 23 मई को एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। बघेलखंड सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट की बैठक में आज शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने की। इस शिविर में मरीजों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच के अलावा ऐसी जांचें भी मुफ्त की जायेंगी जो महँगी हैं। इनमें ब्लड टेस्ट और पैथोलॉजी, एक्स-रे और ईसीजी तथा अल्ट्रासाउंड और ईको शामिल हैं। संस्था के महासचिव डा. कमलाकर सिंह ने बताया कि ट्रस्ट सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में लगातार सक्रिय है। इसके बाद आगे विंध्य की प्रतिभाओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट की वार्षिक पत्रिका 'बघेली दर्पण' का प्रकाशन भी हर साल की तरह किया जाएगा। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे, सभी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में महासचिव डा. कमलाकर सिंह, मो.युनुस, सचिव सुनील शुक्ला, कोषाध्यक्ष सागर श्रीवास्तव तथा कार्यकारिणी सदस्य, पीयूष श्रीवास्तव, कुलवंत सिंह एवं डा. मुकेश मिश्रा, डा. के.पी सिंह, डा. देवेश मिश्रा, डा. सचिन सिंह, सत्येंद्र भदौरिया, डी.आर. सिंह और शिविर के आयोजन में सहयोगी चिरायु हास्पिटल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ट्रैक्टर घोटालाः समय में नहीं मिला जांच प्रतिवेदन

- एडीएम की अध्यक्षता में गठित है जांच टीम
- घोटाले की जांच में बदल चुके हैं चार एडीएम

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी की शाखा गांधीग्राम में 124 ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच कलेक्टर विकास मिश्रा के आदेश पर फिर शुरू तो हुई लेकिन निर्धारित तिथि 8 मई 2026 तक जांच प्रतिवेदन नहीं मिल सका है। दरअसल ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच को पूर्ण करना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ट्रैक्टर ऋण घोटाला के सामने आने के बाद से गठित टीमों के पूर्व में चार एडीएम बदल चुके हैं लेकिन निर्धारित तिथि तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। कारण घोटाले से जुड़े कई दस्तावेजों को ही बैंक स्तर से गायब करा दिया गया है। लिहाजा गठित टीम को जांच पूरी करने के लिए संबंधित कागजात ही नहीं मिल पा रहे हैं। उच्च स्तर पर ट्रैक्टर घोटाले की जांच को दबाने का प्रयास सालों से किया जा रहा है। ट्रैक्टर ऋण घोटाले का मामला वर्तमान कलेक्टर विकास मिश्रा के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा जांच के लिए अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय को जांच टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं जांच टीम के सदस्य में एसडीएम गोपद बनास राकेश शुक्ला, डीएसपी मुख्यालय अमन मिश्रा, गोपद बनास तहसीलदार राकेश शुक्ला, वरिष्ट सहकारी निरीक्षक मदन सिंह उइके एवं वरिष्ट सहकारी निरीक्षक एसपी पाण्डेवा को शामिल किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक विगत 24 अप्रैल 2026 को अपने कक्ष में लेते हुए निर्देशित किया गया था कि समय-सीमा में 124 ट्रैक्टर प्रकरणों की जांच कर 8 मई 2026 तक कलेक्टर द्वारा चाहा गया है। फिर भी निर्धारित तिथि बीतने के बाद भी जांच प्रतिवेदन सामने नहीं आ सका। दरअसल दो करोड़ से ऊपर का ट्रैक्टर घोटाला तीन वर्ष पूर्व सामने आने पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा छः सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई थी। उस दौरान सात दिवस में जांच प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए थे।

जांच टीम में इन्हें किया गया है शामिल

कलेक्टर के निर्देश पर तैयार की गई ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच टीम अपर कलेक्टर के नेतृत्व में गठित की गई है। टीम के सदस्य एसडीएम गोपद बनास, डीएसपी मुख्यालय, तहसीलदार गोपद बनास, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग सीधी, वरिष्ट सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग सीधी को शामिल किया गया है। ट्रैक्टर घोटाले की राशि करीब दो करोड़ रुपए है और इस घोटाले में सहकारी बैंक के कई अधिकारियों एवं ट्रैक्टर एजेंसी संचालकों की संलिप्तता होने के कारण फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह जांच प्रतिवेदन समय पर आएगा कि फिर से इसे ठंडे बस्ते में डालने का सियासी दबाव बढ़ जाएगा।

शत्रु संपत्ति मामले में अदालत से आज़म खान को राहत, बढ़ी हुई धाराओं में मिली तलब जमानत

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बढ़ी हुई धाराओं के तहत उन्हें तलब जमानत प्रदान कर दी है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति प्रकरण में पूर्व में दर्ज मुकदमे में कुछ अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई थीं, जिसके चलते उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद अदालत ने राहत देते हुए तलब जमानत मंजूर कर ली। अदालत के इस फैसले के बाद न्यायालय परिसर में उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि सच्चाई की हमेशा विजय होती है। वहीं विपक्षी पक्ष का कहना है कि मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। गौरतलब है कि शत्रु संपत्ति प्रकरण को लेकर पूर्व में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है और यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब अदालत से मिली इस राहत के बाद राजनीतिक हलकों में फिर से हलचल तेज हो गई है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की जानी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

"संकल्प" अभियान बना जनआंदोलन

- विधायक रीती पाठक की अगुवाई में निकली विशाल नशा मुक्ति रैली, युवाओं ने लिया नशामुक्त समाज का संकल्प

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में नशे के खिलाफ जनजागरूकता को नई दिशा देते हुए मंगलवार को "संकल्प" नशा मुक्त समाज अभियान के तहत भव्य जनआंदोलन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा नगर पालिका परिषद सीधी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सहभागिता कर नशामुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया। सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक के नेतृत्व में पूजा पार्क से गांधी चौक तक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में युवाओं, छात्र-छात्राओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो", "नशा मुक्त युवा, सशक्त भारत" और "न हम नशा करेंगे, न किसी को करने देंगे" जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है, जब हर नागरिक स्वयं से इसकी शुरुआत करे। युवाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी उठानी होगी और गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाना होगा। उन्होंने परिवारों में संवाद बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को समय देना और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना बेहद जरूरी है, ताकि वे गलत संगति और नशे की प्रवृत्ति से दूर रह सकें। विधायक ने नागरिकों से प्रतिदिन योग, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान नशे के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया, जिसने लोगों को नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। इसके बाद गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित जनसमूह ने "नशामुक्त सीधी" का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, पार्षद आनंद परियानी, जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, उपखंड अधिकारी राकेश शुक्ला, उपसंचालक सामाजिक न्याय धनंजय मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं समाजसेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरेंद्र शुक्ला एवं सांदीपनि विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्ति आधारित प्रेरक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए अभियान को प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि नशा मुक्ति केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से चलने वाला जनआंदोलन है, जिसे गांव-गांव तक पहुंचाकर स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा विजन

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चिफ, कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश

कटनीः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर कटनी जिले की समृद्ध खनिज संपदा और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण पोस्ट साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कटनी देश के प्रमुख "माइनिंग कैपिटल" के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि कटनी अब केवल "चूना नगरी" तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक खनन प्रबंधन, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खनिज संपदा के वैज्ञानिक, पारदर्शी और जनहितकारी उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 से खुला निवेश का नया द्वार- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगस्त 2025 में आयोजित "माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0" का उल्लेख करते हुए बताया कि कटनी में 56 हजार 414 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कॉन्क्लेव में देश की बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने सीमेंट, मिनरल प्रोसेसिंग, ऊर्जा, धातु प्रसंस्करण और निर्माण क्षेत्र में निवेश की रुचि दिखाई। इन निवेश प्रस्तावों से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे कटनी औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभरेगा।

"स्वर्ण नगरी" के रूप में विकसित होगा कटनी-मुख्यमंत्री ने कटनी को "कनकपुरी" अर्थात "स्वर्ण नगरी" के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि कटनी की धरती केवल खनिज संपदा का भंडार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की औद्योगिक शक्ति का नया आधार बन रही है। कटनी जिले की स्लीमनाबाद तहसील के इमलिया गांव, जिसे स्थानीय स्तर पर "सुनाही" भी कहा जाता है, में लगभग 3.35 लाख टन स्वर्ण अयस्क मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। लगभग 50 वर्षों तक चले भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद वर्ष 2025-26 में इस खोज को अंतिम रूप दिया गया।

सोने के साथ मिले बहुमूल्य खनिज-विशेषज्ञों के अनुसार इमलिया क्षेत्र में केवल सोना ही नहीं, बल्कि तांबा, जिंक, लेड और चांदी जैसे बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार भी पाए गए हैं। यह खोज कटनी को देश के प्रमुख बहु-खनिज क्षेत्रों में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक मानी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

श्रीलंका में साइबर अपराध में 173 भारतीय, 25 नेपाली नागरिक गिरफ्तार

कोलंबो। श्रीलंकाई पुलिस ने दक्षिणी प्रांत में तीन जगहों पर छापा मारकर 198 विदेशी नागरिकों को संगठित साइबर अपराध में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया है। यह छापे मिडिगामा, हिक्काडुवा और गाले में मारे गए। इन स्थानों पर कथित तौर पर डिजिटल धोखाधड़ी के केंद्रों का संचालन हो रहा था। पुलिस के अनुसार यह संदिग्ध मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनमें 173 भारतीय नागरिक और 25 नेपाली नागरिक शामिल हैं। डेली मिरर अखबार के अनुसार गाले में सबसे ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यहां दो स्थानों से 110 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया। हिक्काडुवा में पुलिस ने डोडंडुवा में एक ठिकाने पर छापा मारकर 35 भारतीयों और 20 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। 43 वर्षीय होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने इन लोगों को रहने की जगह दी थी। पुलिस ने 25 कंप्यूटर, 119 मोबाइल फोन, लगभग 750,000 रुपये नकद और दो वाहन जब्त किए। मिडिगामा पुलिस ने 11 मई को पिनवट्टा इलाके में एक होटल पर छापा मारा और 33 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 28 भारतीय और पांच नेपाली नागरिक शामिल हैं। इस होटल से कुल 83 कंप्यूटर और 198 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। संदिग्धों पर कंप्यूटर अपराध अधिनियम का उल्लंघन करने, बिना वैध वीजा के श्रीलंका में रहने और टूरिस्ट वीजा पर रहते हुए नौकरी करने का आरोप लगाया जाएगा।

लक्षण दिखते ही सबसे अधिक संक्रामक होता है हंटावायरस : डब्ल्यूएचओ

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि क्रूज जहाज पर फैले घातक हंटावायरस संक्रमण में मरीज लक्षण दिखाई देने के शुरुआती समय में सबसे अधिक संक्रामक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी वजह से संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने की सिफारिश की है। डच झंडे वाले क्रूज जहाज एमवी होंडियस पर फैले इस दुर्लभ वायरस संक्रमण से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। जहाज से निकाले गए यात्रियों के अपने-अपने देशों में लौटने के बाद संक्रमण के संभावित फैलाव को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ के महामारी विज्ञान एवं विश्लेषण विभाग के प्रमुख डॉ ओलिवियर ले. पोलैन ने बताया कि बीमारी की शुरुआत में ही संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं, जैसे थकान या हल्का बुखार, लेकिन बाद में स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए लक्षणों का इंतजार किए बिना संभावित संपर्कों को अलग करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज पर मौजूद लगभग 150 लोगों के लिए छह सप्ताह के क्वारंटीन की सिफारिश की है। यह अवधि एंडीज वायरस की अधिकतम ऊष्मायन अवधि के अनुरूप है, जो करीब 42 दिन मानी जाती है। एंडीज वायरस हंटावायरस का ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। कई देशों ने डब्ल्यूएचओ की सलाह मानते हुए सख्त क्वारंटीन व्यवस्था लागू की है। जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ग्रीस ने 45 दिन तक निगरानी रखने का फैसला किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने क्रमशः तीन और दो सप्ताह की न्यूनतम निगरानी अवधि तय की है। हालांकि अमेरिका ने अपने लौटे यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन का स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे जोखिमपूर्ण बताया है। डॉ पोलैन के अनुसार क्रूज जहाज का बंद वातावरण संक्रमण फैलने के लिए अनुकूल साबित हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सीमित स्थान में साथ रह रहे थे। इसी कारण सामान्य परिस्थितियों की तुलना में संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई।

बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत को ईडी ने गिरफ्तार किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और TMC नेता सुजीत बोस को नगर निगम भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अरेस्ट किया। सुजीत अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सुबह करीब 10:30 बजे ED ऑफिस पहुंचे थे। उनसे करीब 10 घंटे पूछताछ की गई, फिर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। सुजीत बोस पर 2014-2018 के बीच साउथ दमदम नगर निगम में करीब 150 लोगों की अवैध भर्ती कराने का आरोप है। कहा जाता है कि सुजीत ने इसके बदले पैसे और फ्लैट लिए थे। सुजीत उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिधाननगर से तीन बार के विधायक रहे सुजीत बोस हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के शरदवत मुखर्जी से 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। सुजीत बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ED के कई नोटिस मिले। जिनमें से एक 6 अप्रैल को मिला था। इसी दिन नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। उन्होंने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और चुनाव प्रचार में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए ED के सामने पेश होने से छूट मांगी थी। चुनावों के बाद बोस 1 मई को CGO कॉम्प्लेक्स में ED अधिकारियों के सामने पेश हुए। 11 दिन बाद दोबारा पेशी में सुजीत को अरेस्ट कर लिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों पर CBI की तरफ से FIR दर्ज किए जाने के बाद ED ने 2 जनवरी 2024 और अक्टूबर 2025 में सुजीत बोस के ठिकानों पर छापेमारी की।

पंजाब विजिलेंस से जुड़े 20 लाख के रिश्वत मामले में तीन रंगेहाथों गिरफ्तार, रीडर राणा फरार

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो से जुड़े 20 लाख रुपये के रिश्वत मामले में तीन आरोपितों को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। इनमें दो बिचौलिए और एक सहयोगी शामिल हैं। सीबीआई ने बताया कि पंजाब राज्य कर अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विकास उर्फ विक्की गोयल और उसका पुत्र राघव गोयल ने उसके खिलाफ लंबित शिकायत को बंद कराने के लिए 20 लाख रुपये की मांग की थी। दोनों आरोपित डीजी (विजिलेंस), पंजाब के रीडर ओपी राणा के लिए मध्यस्थता कर रहे थे। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई और रिश्वत की मांग 20 लाख से घटाकर 13 लाख रुपये कर दी गई। राणा के लिए एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड7 मोबाइल फोन भी मांगा गया। 11 मई को चंडीगढ़ में सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपित अंकित वाधवा को 13 लाख रुपये और मोबाइल फोन लेते रंगे हाथों दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान राघव गोयल, विकास उर्फ विक्की गोयल और ओपी राणा मौके से भाग निकले। बाद में सीबीआई टीम ने पीछा कर राघव गोयल, विकास गोयल और उनके दो गनमैन को अंबाला के पास पंजाब-हरियाणा सीमा पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राणा अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सीबीआई ने बताया कि आरोपितों के आवास पर तलाशी में 9 लाख रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। जांच में यह भी सामने आया कि राणा और निजी आरोपितों के बीच लंबित सतर्कता मामलों की संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान हो रहा था। पंजाब पुलिस के गनमैन की भूमिका भी जांच के दायरे में है। गिरफ्तार आरोपियों को चंडीगढ़ की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

अर्कांडिया की मेयर का इस्तीफा, चीन की एजेंट होने का जुर्म स्वीकार किया

सैक्रामेंटो। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के अर्कांडिया शहर की महापौर (मेयर) एलीन वांग ने चीन के एजेंट के रूप में काम करने का गुनाह स्वीकार करते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसकी पुष्टि की है। संघीय अभियोजकों ने बताया कि 58 वर्षीय वांग और उस समय उनके तत्कालीन मंगेतर याओनिंग माइक सन पर चीन के सरकारी अधिकारियों के इशारे पर अमेरिका में काम करने का आरोप है। 65 वर्षीय सन पिछले साल अक्टूबर में एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने के बाद चार साल की जेल की सजा काट रहा है। सन को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उसे फरवरी में सजा सुनाई गई। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक याचिका में वांग ने खुद पर लगे आरोप अदालत में स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इस अपराध के लिए उन्हें अधिकतम 10 साल जेल की सजा हो सकती है। उम्मीद है कि एलीन वांग लॉस एंजिल्स की संघीय अदालत में भी अपना अपराध स्वीकार कर लेंगी। वांग नवंबर 2022 में अर्कांडिया सिटी काउंसिल के लिए चुनी गई थीं। यह काउंसिलपांच सदस्यीय शासी निकाय है और इसमें महापौर का चयन बारी-बारी से होता है।

सुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी

7 अफसरों की एसआईटी गठित, बिहार-यूपी से गिरफ्तार 3 आरोपी 13 दिन की पुलिस कस्टडी में

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब CBI करेगी। CBI ने केस अपने हाथ में लेते ही 7 मेंबर्स की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। टीम की अगुआई DIG रैंक के अधिकारी करेंगे। इस केस में अब तक बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को तीनों को नॉर्थ 24 परगना के बारासात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बंगाल चुनाव नतीजों के दो दिन बाद, 6 मई को नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम में 42 साल के चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर ने उनकी कार रोककर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें उन्हें सीने और पेट में तीन गोलियां लगीं।

बिहार और यूपी से पकड़े गए 3 आरोपी: पुलिस ने मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया है। मयंक और विक्की को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से 10 मई को पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद राज सिंह का एक पोस्टर सामने आया है। इसमें उसने खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताया है। उसके फेसबुक अकाउंट में मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ की तस्वीर है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के साथ उसकी रील भी है। अदालत ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सबूत मिटाने से जुड़ी धारा जोड़ने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों की कार हत्या से पहले बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी। यहां कार में मौजूद एक व्यक्ति ने UPI के जरिए टोल पेमेंट किया था। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की और फिर बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों की पहचान को टोल प्लाजा के CCTV फुटेज और वाहन की तस्वीरों से मैच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों ने पहचान छिपाने और मूवमेंट छुपाने के लिए कई तरीके अपनाए थे। बंगाल पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद रथ की हत्या में सुपारी किलर के शामिल होने की आशंका जताई थी। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि रथ की हत्या प्लानिंग के तहत की गई और इसमें प्रोफेशनल शूटर शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार जब्त की, जिससे रथ की स्कॉर्पियो का पीछा किया गया था। कार की नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार का चेसिस और इंजन नंबर मिटाया गया था।

केरलम के सीएम का ऐलान 24 घंटे के भीतर

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम

- राहुल से मिलने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का दावा, वेणुगोपाल पहली पसंद

केरलम के अगले सीएम के नाम की घोषणा अगले 24 घंटे में हो सकती है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. मुरलीधरन ने राहुल गांधी से मिलने के बाद यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक मुख्यमंत्री के नाम सामने आ जाएगा। मुरलीधरन ने बताया कि सोनिया गांधी के आवास '10 जनपथ' पर राहुल ने केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ अगले CM के नाम पर चर्चा की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम को बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे हैं। उनके आने के बाद एक और दौर की बातचीत होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला होगा। 2026 केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को ही आ गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन को 140 में से 102 सीटें मिली थीं। बंगाल, असम, तमिलनाडु के सीएम तय, केरलम में 9 दिन बाद भी स्सपेंस

4 मई को 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद बंगाल, असम और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पुडुचेरी में सीएम रंगासामी बुधवार को शपथ लेंगे। केरलम को अपने नए CM का इंतजार है। कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं। राहुल ने दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 75-80% सदस्यों ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया। वीडी सतीशन को 6 विधायकों का समर्थन मिला।

नीट परीक्षा रद्द होना युवाओं के भविष्य के साथ अपराध : राहुल गांधी

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट व्यवस्था ने कुचल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार ने युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है।

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की, लेकिन बदले में उन्हें मिला पेपर लीक और भ्रष्टाचार। यह केवल नाकामी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है।

उन्होंने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर शिक्षा परिश्रम से नहीं बल्कि पैसे और पहुंच से तय मिलेगी तो फिर शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। एनटीए ने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड का कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा।

उदयनिधि स्टालिन बोले- सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, यह लोगों को बांटता है

एजेंसी, चेन्नई

- पहले डेंगू-मलेरिया बताया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था

तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए। यह लोगों को बांटता है। उन्होंने पहले 2023 में भी सनातन को डेंगू, मलेरिया बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। उदयनिधि ने विजय के शपथ ग्रहण समारोह का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु के पारंपरिक तमिल आह्वान गीत 'तमिल थाई वाझथु' को कार्यक्रम में तीसरे स्थान पर रखा गया, जबकि परंपरा के मुताबिक इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। उदयनिधि ने कहा- हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमिलनाडु में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में तमिल थाई वाझथु को पहला स्थान मिलना चाहिए। दरअसल 10 मई को विजय के शपथ ग्रहण में सबसे पहले वंदे मातरम बजा। फिर जन गण मन बजा। इसके बाद तमिल राज्य गीत बजाया गया था।

उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया बताया था: उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। उदयनिधि ने कहा- सनातन धर्म मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना जैसा है, जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। विवाद बढ़ने पर उदयनिधि ने कहा कि मैं हिंदू धर्म नहीं सनातन प्रथा के खिलाफ हूं। तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। अतीत में कई मौकों पर अंबेडकर, पेरियार भी इसके बारे में बोलते रहे हैं। सनातन धर्म के कड़े विरोध के कारण ही महिलाएं घर से बाहर निकल सकीं और सती जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुईं। उन्होंने कहा- वास्तव में, DMK की स्थापना ही उन सिद्धांतों पर हुई थी जो ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2025 को उदयनिधि स्टालिन को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टालिन ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। स्टालिन कोई आम आदमी नहीं है। उन्हें बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। CM विजय ने तमिलनाडु में 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया: CM विजय ने मंगलवार को 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। अगले दो हफ्ते के अंदर पूजा स्थलों के पास की 276 दुकानें, शिक्षण संस्थानों के पास की 186 दुकानें और बस स्टैंड के पास की 255 दुकानें बंद कर दी जाएंगी।

विधायी प्रक्रियाओं में एकरूपता अब संस्थागत आवश्यकता बन चुकी है : विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी, मैसूर/नई दिल्ली

"डिजिटल विधानसभाओं और प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था के इस युग में विधायी प्रक्रियाओं में एकरूपता अब केवल अपेक्षित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक संस्थागत आवश्यकता बन चुकी है। प्रक्रियाओं के समन्वित नियम पारदर्शिता, कार्यपालिका की जवाबदेही तथा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में समरूपता को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे," यह बात दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित "विधायी निकायों के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के समान मॉडल नियम तैयार करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की समिति" की प्रारंभिक बैठक में कही। इस समिति की बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई है।

विजेंद्र गुप्ता ने पटना में हुए 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी संस्थागत सुधार है, जो देशभर की विधानसभाओं के कार्य संचालन में अधिक समन्वय, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 208 राज्यों की विधानसभाओं को भी समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 33 दिल्ली विधानसभा को अपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने का अधिकार देती है, बशर्ते वे लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधान विधानसभाओं को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली विनियमित करने की संप्रभुता प्रदान करते हैं, साथ ही व्यापक लोकतांत्रिक हित में स्थापित संसदीय परंपराओं, प्रक्रियाओं एवं नवीनताओं को स्वेच्छा से अपनाने का अवसर भी देते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देशभर की विधानसभाओं के नियमों में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किए गए और समय-समय पर लोकतांत्रिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें परिवर्तन होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य विधानसभाओं ने ऐतिहासिक रूप से लोकसभा के नियमों के व्यापक ढांचे का अनुसरण किया है, हालांकि स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

यमुना नदी में छह लोग डूबे, चार की मौत व दो को बचाया गया

एजेंसी, आगरा

उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को यमुना नदी में नहाने के दौरान छह लोग डूब गए। रेस्क्यू के दौरान दो लोगों को बचालिया गया लेकिन चार लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है।

बताया गया कि सोमवार की शाम आगरा के विद्यापुरम फाउंड्री नगर निवासी सौरभ पुत्र भूरी सिंह नाई की पुत्री नित्या (एक वर्ष) के जन्मदिन का कार्यक्रम था। इस बर्थडे पार्टी में कुछ रिश्तेदार बाहर से आए थे। मंगलवार को सभी यमुना नदी नहाने गये। नहाने के दौरान दोहपर करीब एक बजे दोपहर थाना क्षेत्र कमला नगर अंतर्गत यमुना नदी के बल्केश्वर घाट पर दो बच्चे नदी की गहराई की ओर जाने लगे और डूबने लगे। बच्चों को बचाने गए अन्य लोग भी डूबने लगे। देखते ही देखते कान्हा (22) पुत्र रिंकू, महक (19) पुत्री कालीचरण निवासीगण ग्राम कुंजनपुर थाना सादाबाद हाथरस, रिया उम्र (17) पुत्री मनोज निवासी तारसी मथुरा, विक्की (11) पुत्र राकेश, काजल (17) पुत्री भूरी सिंह निवासी विद्यापुरम फाउंड्री नगर और अंशु (13) पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम कुंजनपुर थाना सादाबाद हाथरस डूब गये। डूबते लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग नदी में कूद गये। सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं पीएसी पहुंच गई। इन लोगों की मदद से पुलिस और पीएसी की गोताखोरों ने नदी में डूबे लोगों में से पांच लोगों को बाहर निकाल लिया। पुलिस और स्थानीय लोगो की मदद से काजल, अंशु को निकाल लिया गया है लेकिन कान्हा, महक, रिया की मौत हो गई।

बंगाल में एसआईआर कराने वाले अधिकारी चीफ सेक्रेटरी बने

एजेंसी, कोलकाता

सुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में SIR कराने वाले चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। मनोज की देखरेख में विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट में विशेष गहन संशोधन (SIR) कराया गया था। इसमें मतदाता सूची से लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम हट गए थे। इसके अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता को भी मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रत को बंगाल में SIR के दौरान ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया X पर लिखा, ये नियुक्तियां ECI और BJP के बीच खुली मिलीभगत और सांठगांठ को दर्शाती हैं। अब तो इस मिलीभगत को छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि ECI निष्पक्ष नहीं था और उसने पूरी तरह से BJP को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम किया। रमेश ने कहा, चुनाव के दौरान 27 लाख लोगों को वोट करने से रोक दिया गया। ECI ने BJP को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया। TMC नेता साकेत गोखले ने इस कदम को 'बेहद बेशर्मी भरा बताया। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने तंज वाले लहजे में इसे एक 'संयोग' कहा। X पर अपनी पोस्ट में, गोखले ने कहा कि इस कदम से पता चलता है कि BJP और ECI "चुनाव चुराने के मामले में खुलेआम सामने आ रहे हैं"।

पश्चिम एशिया संकट पर पवार बोले- मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं

पीएम की गोल्ड न खरीदने की अपील पर ज्वेलर्स ने कहा- रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा

एजेंसी, नई दिल्ली

शरद पवार ने मंगलवार को पश्चिम एशिया संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मामलों में सभी दलों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है। पवार ने X पर लिखा- पीएम मोदी ने जनता से सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल कम खर्च करने की अपील की है। इससे अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इन घोषणाओं से आम लोगों और कारोबारियों में बेचैनी बढ़ी है। ज्वेलरी काउंसिल का कहना है कि पीएम को उनसे बात करनी चाहिए थी। पीएम की अपील से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। दरअसल, पीएम मोदी ने लगातार दो दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। हालांकि, इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 69 दिन का कच्चे तेल और 45 दिन का LPG स्टॉक है।

ज्वेलर्स बोले- रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा: महाराष्ट्र स्वर्णकार सराफा महामंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कवाले ने कहा देशभर के ज्वेलर्स में चिंता बढ़ गई है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल और महाराष्ट्र बोर्ड से चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार को पहले हमारी राय लेनी चाहिए थी। कवाले ने कहा- अगर कारोबार बंद हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इन लोगों को रोजगार देगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के गुजरात अध्यक्ष नैनेश पच्छीगर ने कहा कि हम देश के साथ हैं और 'नेशन फर्स्ट' में भरोसा रखते हैं। लेकिन ज्वेलरी कारोबार से छोटे और मझोले स्तर के लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। सरकार को फैसला लेते समय इनके रोजगार और आगे पड़ने वाले असर का भी ध्यान रखना चाहिए।

नीट-यूजी परीक्षा 2026 रद्द-3 मई 2026 को आयोजित पेपर लीक, परीक्षा माफिया और एनटीए की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा संकट -व्यापक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» क़्या पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 जिसे एंटी पेपर लीक कानून कहा जाने लगा निष्प्रभावी साबित हुआ?

» नीट-यूजी 2026 सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द- छात्र और अभिभावक सदमे में कि आखिर वास्तविक मास्टरमाइंड कानून से कैसे बार-बार खिलवाड़ करते हैं और बच जाते हैं ? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बारफिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां करोड़ों विद्यार्थियों का विश्वास,अभिभावकों की उम्मीदें और देश की प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली की साख एक साथ कठघरे में खड़ी हो गई है। 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रद्द किए जाने के फैसले ने पूरे देश में अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है।परीक्षा रद्द होने के पीछे कथित पेपर लीक,वायरल गेस पेपर, संगठित परीक्षा माफिया और प्रश्नपत्र के बड़े हिस्से के असली परीक्षा से मेल खाने के आरोपों ने शिक्षा जगत को झकझोर दिया है। केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है,जबकि देश के अनेक शहरों में छात्र आंदोलन,प्रदर्शन और विरोध मार्च शुरू हो चुके हैं।दिल्ली से लेकर पटना,जयपुर, लखनऊ,भोपाल और कोटा तक विद्यार्थियों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लाखों छात्र यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी वर्षों की मेहनत का मूल्य क्या है, यदि परीक्षा प्रणाली ही सुरक्षित नहीं रह गई है। यह केवल एक परीक्षा रद्द होने की घटना नहीं है, बल्कि भारत की पूरी प्रतिस्पर्धी परीक्षा व्यवस्था पर गहरा अविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रीय संकट बन चुका है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि नीट-यूजी 2026 विवाद ने एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। पिछले लगभग पांच वर्षों में अनेक राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी तकनीकी गड़बड़ियां हुईं,कभी परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था पर सवाल उठे और कभी परिणामों की पारदर्शिता पर बहस छिड़ी। नीट, यूजीसी नेट, जेईई और कई भर्ती परीक्षाओं में समय-समय पर सामने आए विवादों ने यह धारणा मजबूत की है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामियां मौजूद हैं। इस बार स्थिति इसलिए और अधिक विस्फोटक हो गई क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनलों और कुछ निजी नेटवर्कों पर एक कथित गेस पेपर वायरल हुआ था। बाद में जांच एजेंसियों द्वारा यह दावा सामने आया कि वायरल सामग्री के लगभग 120 से 125 प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से हूबहू मेल खाते थे। यदि यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है, तो यह केवल लीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठित परीक्षा अपराध का उदाहरण माना जाएगा। साथियों बात अगर हम साल 2018 में स्थापित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का उद्देश्य को समझने की करें तो देश में प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी,आधुनिक और निष्पक्ष बनाना था। एजेंसी को तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली, डिजिटल निगरानी और केंद्रीकृत प्रबंधन के जरिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार का बड़ा मॉडल माना गया था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार एनटीए ने स्थापना के बाद 240 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन किया, जिनमें 5.4 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल हुए।लेकिन उपलब्धियों के साथ-साथ विवादों की सूची भी लगातार बढ़ती गई। संसद में वर्ष 2024 में दिए गए सरकारी जवाब में यह स्वीकार किया गया था कि एनटीए को अब तक कम से कम 16 परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। यह संख्या केवल प्रशासनिक चुनौतियों का संकेत नहीं देती, बल्कि यह बताती है कि भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में परीक्षा प्रबंधन कितनी जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया बन चुका है। साथियों बात अगर हम नीट- यूजी से जुड़ा विवाद इसको समझने की करें तो यह नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस परीक्षा कीविश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। 2024 में भी नीट परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब परिणामों में असामान्य अंक, ग्रेस मार्क्स,परीक्षा केंद्रों की अनियमितताएं और पेपर लीक के आरोपों ने राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया था। उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और केंद्र सरकार को व्यापक सफाई देनी पड़ी। हालांकि परीक्षा पूरी तरह रद्द नहीं हुई थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी थी। उसी वर्ष यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को पेपर लीक की आशंकाओं के चलते रद्द करना पड़ा था। इससे पहले भी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी थीं। कई राज्यों में संगठित गिरोह करोड़ों रुपये लेकर उम्मीदवारों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने, सॉल्वर बैठाने और डिजिटल माध्यमों से परीक्षा में धोखाधड़ी कराने के आरोपों में पकड़े गए। साथियों बात अगर हम पेपर लीक रोकने के लिए अधिनियम की करें तो लगातार बढ़ते विवादों और राष्ट्रीय स्तरपर हो रही आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट लागू किया,जिसे आम बोलचाल में एंटी पेपर लीक कानून कहा जाने लगा। संसद ने फरवरी 2024 में इस कानून को पारित किया और 21 जून 2024 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि संगठित परीक्षा अपराध अब इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि केवल राज्य स्तरीय कानूनों से इससे निपटना संभव नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानूनी ढांचा आवश्यक था।लेकिन अब सटीक विडंबना यह है कि इतने सख्त कानून के लागू होने के बावजूद नीट-यूजी 2026 जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द करना पड़ा। इससे छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि आखिर वास्तविक मास्टरमाइंड कौन हैं और वे कानून से बच कैसे जाते हैं।एंटी पेपर लीक कानून के प्रावधान अत्यंत कठोर माने जाते हैं। इस कानून के तहत पेपर लीक, फर्जी परीक्षा संचालन, डिजिटल हैकिंग, सॉल्वर गैंग चलाना या उम्मीदवार की जगह किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा दिलाना गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। संगठित पेपर लीक गिरोह चलाने वालों को 5 से 10 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी परीक्षा केंद्र, आईटी कंपनी, प्रिंटिंग एजेंसी या अन्य सेवा प्रदाता की मिलीभगत सामने आती है, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। कानून केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि गंभीर मामलों की जांच सीबीआई जैसी एजेंसियों को सौंपी जा सके और विशेष अदालतों के माध्यम से तेज सुनवाई कराई जा सके। पहली नजर में यह कानून बेहद कठोर और व्यापक दिखाई देता है,लेकिनवास्तविक चुनौती कानून बनाने से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। साथियों बात अगर हम विशेषज्ञों के राय को समझने की करें तो वे मानते हैं कि भारत में पेपर लीक अब केवल स्थानीय अपराध नहीं रह गया है, बल्कि यह संगठित आर्थिक उद्योग का रूप ले चुका है। इसमें शिक्षा माफिया कोचिंग नेटवर्क, तकनीकी विशेषज्ञ,साइबर अपराधी,प्रिंटिंग चैन से जुड़े लोग और कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक तत्वों की संभावित मिलीभगत होती है। यही कारण है कि कई मामलों में जांच एजेंसियां छोटे स्तर के एजेंटों तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन वास्तविक मास्टरमाइंड तक पहुंचना बेहद कठिन साबित होता है। परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसकी प्रिंटिंग,पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन,डिजिटलट्रांसमिशन और परीक्षा केंद्रों तक वितरण की लंबी श्रृंखला होती है। यदि किसी एक स्तर पर भी सुरक्षा चूक हो जाए,तो पूरी परीक्षा खतरे में पड़ सकती है।

साथियों बात अगर हम डिजिटल योग की करें तो डिजिटल तकनीक ने जहां परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया है, वहीं अपराधियों को भी नए हथियार दे दिए हैं। पहले पेपर लीक मुख्यतः फोटोकॉपी या भौतिक दस्तावेजों तक सीमित रहता था,लेकिन अब एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप टेलीग्राम चैनल, क्लाउड स्टोरेज और डार्क वेब जैसे माध्यमों का उपयोग बढ़ गया है। साइबर अपराधी मिनटों में हजारों लोगों तक प्रश्नपत्र पहुंचा सकते हैं। जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि मूल स्रोत कहां था और जानकारी किस चैनल से फैली। कई बार गेस पेपर के नाम पर प्रश्नपत्र प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कानूनी जांच और अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि आरोपी यह तर्क देते हैं कि वह केवल संभावित प्रश्नों का संकलन था। लेकिन यदि बड़ी संख्या में प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खा जाएं, तो संदेह स्वतः गहरा जाता है।नीट-यूजी 2026 मामले में भी यही हुआ। परीक्षा से पहले कुछ ऑनलाइन समूहों में वायरल सामग्री को पहले सामान्य "गेस पेपर" माना गया, लेकिन बाद में जांच में कथित रूप से यह सामने आया कि 120 से अधिक प्रश्न वास्तविक पेपर से मेल खाते थे। यही वह बिंदु था, जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। लाखों विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अनुचित लाभ मिला। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत और मानसिक तनाव के बाद यदि परीक्षा की निष्पक्षता ही समाप्त हो जाए, तो मेहनती छात्रों का भविष्य ग्रुप से असुरक्षित हो जाता है। साथियों बात अगर हम इस पूरे विवाद का सबसे बड़ासामाजिक प्रभाव छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ा है इसको समझने की करें तो,नीट जैसी परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं होती, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, आर्थिक निवेश और भावनात्मक संघर्ष से जुड़ी होती है। अनेक छात्र वर्षों तक कोचिंग लेते हैं, परिवार अपनी बचत खर्च करते हैं और छात्र अत्यधिक मानसिक दबाव के बीच तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने का अर्थ केवल पुनर्परीक्षा नहीं होता,बल्कि यह छात्रों के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं पर गहरा आघात होता है। कई छात्र पहले ही लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव से गुजरते हैं। ऐसे में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाएं उनके भीतर व्यवस्था के प्रति भयंकर अविश्वास पैदा करती हैं। साथियों बात अगर हम राजनीतिक स्तरपर भी यह मुद्दा तेजी से उभर रहा है। इसको समझने की करें तो विपक्षी दल केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कठोर कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जनमानस में यह धारणा मजबूत हो रही है कि हर बार परीक्षा रद्द होने के बाद केवल जांच और गिरफ्तारियों की खबरें आती हैं, जबकि कुछ समय बाद मामला धीमा पड़ जाता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार फास्ट ट्रैक न्याय की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक दोषियों को त्वरित और सार्वजनिक सजा नहीं मिलेगी, तब तक परीक्षा माफिया का मनोबल नहीं टूटेगा। साथियों बात अगर हम भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव भी इस समस्या की जड़ में मौजूद है इसको समझने की करें तो, नीट परीक्षा में हर वर्ष लाखों छात्र कुछ हजार मेडिकल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सीमित अवसर और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षा माफिया के लिए बड़ा बाजार तैयार करते हैं। करोड़ों रुपये लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने,सॉल्वर बैठाने और फर्जी उम्मीदवारों के माध्यम से सीट दिलाने का अवैध कारोबार इसी दबाव से फलता-फूलता है। जब सफलता और असफलता के बीच केवल कुछ अंक का अंतर हो, तब कुछ लोग अनुचित रास्ते अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वह सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति है, जिसने पेपर लीक उद्योग को बढ़ावा दिया है।विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं हैं। परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की भी अत्यंत आवश्यकता है। प्रश्नपत्र निर्माण और वितरण प्रणाली को अधिक विकेंद्रीकृत तथा एन्क्रिप्टेड बनाना होगा। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग बढ़ाना होगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को परीक्षा प्रबंधन का स्थायी हिस्सा बनाना आवश्यक है। साथ ही प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक चैन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही स्पष्ट करनी होगी।इस पूरे विवाद ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है क्या भारत की परीक्षा प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुकी है? जब करोड़ों छात्रों की परीक्षा एक ही एजेंसी के माध्यम से आयोजित होती है, तब किसी एक स्तर की विफलता का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक बहुस्तरीय और क्षेत्रीय रूप से सुरक्षित बनाया जाना चाहिए ताकि किसी एक बिंदु पर हुई चूक राष्ट्रीय संकट में न बदल जाए।

अतः अगर हम अपरूप पूरे ववरिण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने की घटना केवल एक प्रशासनिक असफलता नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास संकट का प्रतीक है जो धीरे-धीरे भारत की प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली को घेर रहा है।यदि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार प्रश्न उठते रहेंगे, तो इसका असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और युवाओं के भविष्य पर भी पड़ेगा। करोड़ों छात्र यह महसूस करने लगेंगे कि मेहनत से अधिक प्रभावशाली नेटवर्क और अवैध साधन निर्णायक बनते जा रहे हैं। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत खतरनाक है। आज सटीक आवश्यकता केवल दोषियों की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा ढांचे के पुनर्मूल्यांकन की है। सरकार, जांच एजेंसियों, शिक्षा विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा संस्थानों और समाज को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां परीक्षा केवल ज्ञान और योग्यता की प्रतिस्पर्धा बने, अपराध और माफिया नेटवर्क का मैदान नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो हर नई परीक्षा के साथ छात्रों के मन में एक ही प्रश्न उठेगा क्या इस बार भी पेपर लीक होगा? जो रेखांकित करना बहुत जरूरी है

-संकलनकर्ता लेखक
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार
साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय
लेखक चिंतक कवि संगीत
माध्यमा सीए(एटीसी)
एडवोकेट किशन सनमुखदास
भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

क्या हम आर्थिक आपातकाल की दहलीज पर हैं?

लेखक - दिलीप कुमार पाठक

पीएम मोदी ने हैदराबाद के मंच से देशवासियों के सामने सात अपीलें रखीं, जो केवल राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के बदलते मिजाज का एक बड़ा संकेत था। मोदी का यह कहना कि एक साल तक सोना खरीदने से बचें, विदेशी यात्राएं टालें और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें, सुनने में तो नागरिकों से किया गया एक साधारण अनुरोध लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे आर्थिक अर्थ बेहद गहरे और गंभीर हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कहना कि ये अपीलें सरकार की नाकामियों का सबसे बड़ा कबूलनामा हैं, राहुल का यह कहना कोई छोटी बात नहीं है। क्या वाकई भारत किसी बड़े आर्थिक भंवर की ओर बढ़ रहा है या फिर यह आने वाले किसी वैश्विक तूफान से पहले की महज एक सावधानी है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को 120 डॉलर प्रति बैरल के पार हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90 प्रतिशत तेल आयात करता है, और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो उसका सीधा असर हमारी जेब और देश के खजाने पर पड़ता है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो मई 2026 की शुरुआत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 690 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया है। यह गिरावट इसलिए चिंता पैदा करती है क्योंकि महज तीन महीने पहले हम 728 अरब डॉलर पर थे। दूसरी ओर, डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि हर वह चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी का यह तर्क वाज़िब है कि 12 साल के लंबे शासन और आत्मनिर्भर भारत के ढोल पीटने के बावजूद, हम आज भी इतने कमजोर क्यों हैं कि एक बाहरी युद्ध की आहट मात्र से हमें अपनी जीवनशैली बदलने की सलाह दी जा रही है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पिछले दशक में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर उस स्तर पर काम नहीं किया कि हम ऐसे वैश्विक झटकों को मजबूती से सह सकें। जब सरकार जनता से कहती है कि वे सोना न खरीदें या अपनी गाड़ियां कम चलाएं, तो वह असल में अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता का बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल रही होती है। यह तर्क भी अपनी जगह सही है कि महंगाई को नियंत्रित करना और रुपये को संभालना पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है, न कि नागरिकों की मजबूरी। एक आम करदाता यह पूछने का हक रखता है कि भारी-भरकम टैक्स देने के बाद भी उसे संकट के समय त्याग करने को क्यों कहा जाता है? हालाँकि नजरअंदाज करना बेमानी होगा। दुनिया के आर्थिक इतिहास को देखें तो समझ आता है कि किसी भी बड़े संकट की घड़ी में केवल सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं होतीं, वहां जन-भागीदारी की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। सरकार का तर्क यहां व्यावहारिक नजर आता है। भारत में सोना और कच्चा तेल दो ऐसी चीजें हैं, जो हमारे कीमती विदेशी मुद्रा यानी डॉलर को सबसे ज्यादा देश से बाहर भेजते हैं। अगर देश समाज एक साल के लिए सोने का मोह त्याग दे और तेल की खपत में थोड़ी भी कमी लाए, तो देश अरबों डॉलर बचा सकता है। यह बचत सीधे तौर पर रुपये को गिरने से रोकेगी। हमने अपने पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सड़क पर आते देखा है।

दम घोंटता लोकतंत्र : क्या भारतीय चुनाव व्यवस्था पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत हैं?

सैयद इसरार हुसैन

भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और लोकतांत्रिक संस्थाएँ देश की व्यवस्था को संचालित करती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र की जिस मजबूत परंपरा को विकसित किया, वह विश्व के लिए एक उदाहरण मानी जाती रही है।किन्तु वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र के सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थाओं की विश्वसनीयता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर लगातार उठ रहे विवाद लोकतंत्र की गुणवत्ता पर बहस को और गहरा कर रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा चुनावों में धांधली, प्रशासनिक दुरुपयोग और ईवीएम में संभावित गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित रह गया है, या वास्तव में जनता का विश्वास उसकी आत्मा बना हुआ है?

लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, विश्वास की व्यवस्था है-लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास होता है। यदि नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि उनकी आवाज़ और वोट का महत्व कम हो रहा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है। चुनाव केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता और व्यवस्था के बीच भरोसे का संबंध होते हैं। आज देश में कई विपक्षी दल चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा, मतगणना प्रक्रिया, चुनावी एजेंसियों की निष्पक्षता और सरकारी मशीनरी के संभावित दुरुपयोग को लेकर लगातार बहस हो रही है। कई बार चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष यह आरोप लगाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही। हालाँकि, भारत निर्वाचन आयोग और सरकार लगातार यह दावा करते रहे हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि वीवीपैट (VVPAT) जैसी व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। इसके बावजूद विपक्ष और नागरिक समाज के एक वर्ग की शंकाएँ समाप्त नहीं हो पा रही हैं। यही स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

ईवीएम विवाद और लोकतांत्रिक विश्वास का संकट-ईवीएम मशीनों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह बहस अधिक तीखी हुई है। कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि मशीनों में तकनीकी हस्तक्षेप संभव है या चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई है।

यह भी सत्य है कि अब तक किसी बड़े स्तर पर ईवीएम हैकिंग का प्रमाण आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी लोकतंत्र केवल कानूनी प्रमाणों पर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर चलता है। यदि बड़ी संख्या में नागरिक और राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त करने लगें, तो यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग केवल तकनीकी स्पष्टीकरण देने तक सीमित न रहे, बल्कि अधिक पारदर्शिता, स्वतंत्र ऑडिट और सभी राजनीतिक दलों के साथ खुले संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करे। लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना निष्पक्ष चुनाव कराना।

राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी माहौल-वर्तमान समय में चुनावी राजनीति अत्यधिक आक्रामक और ध्रुवीकृत होती जा रही है। चुनावी भाषणों में व्यक्तिगत हमले, धार्मिक और जातीय मुद्दों का अत्यधिक उपयोग तथा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार लोकतांत्रिक वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष सरकारी संसाधनों और एजेंसियों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करता है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को निराधार बताता है। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम नागरिक के मन में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर संदेह बढ़ना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन यदि राजनीतिक संघर्ष अविश्वास और संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े करने तक पहुँच जाए, तो लोकतांत्रिक संतुलन कमजोर पड़ने लगता है।

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी आवश्यक-किसी भी लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत और प्रभावी विपक्ष से भी तय होती है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार से जवाबदेही मांगना और जनता के मुद्दों को उठाना होता है।

यदि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए या उन्हें केवल राजनीतिक शोर मान लिया जाए, तो लोकतंत्र की संवाद प्रक्रिया कमजोर होती है। वहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखे, ताकि लोकतांत्रिक विमर्श गंभीर और विश्वसनीय बना रहे।

चुनाव आयोग और संस्थाओं की भूमिका-भारत निर्वाचन आयोग देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में आयोग पर यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह हर राजनीतिक दल और नागरिक के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूर्ण विश्वास कायम करे।

चुनाव सुधारों के अंतर्गत अधिक वीवीपैट मिलान, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता, डिजिटल प्रचार पर निगरानी और स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट जैसी व्यवस्थाएँ लोकतंत्र को और मजबूत बना सकती हैं। लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है।

निष्कर्ष-भारतीय लोकतंत्र आज एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास से जुड़ा विषय हैं। यदि जनता के मन में यह भावना पैदा होने लगे कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हैं, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। सरकार, चुनाव आयोग, विपक्ष, मीडिया और नागरिक समाज—सभी की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखें। असहमति और सवाल लोकतंत्र के दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी शक्ति हैं। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा, जब चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा अटूट बना रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल मशीनों से नहीं चलता, वह जनता के विश्वास और संविधान की आत्मा से जीवित रहता है।

भारत का सोना: "डेड एसेट" या करोड़ों लोगों की आर्थिक जीवनरेखा?

लेखक - भूपेन्द्र गुप्ता

भारत में जब भी अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है, सरकार और नीति निर्धारकों की ओर से एक बात बार-बार कही जाती है—देश को सोने की खपत कम करनी चाहिए। तर्क दिया जाता है कि सोने का अत्यधिक आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है, चालू खाता घाटा बढ़ाता है और निवेश को "उत्पादक क्षेत्रों" से हटाकर निष्क्रिय संपत्ति में बदल देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत में सोना वास्तव में केवल एक "डेड एसेट" है? या फिर यह करोड़ों गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक जीवनरेखा बन चुका है? तथ्य बताते हैं कि भारत में सोने को केवल आभूषण या विलासिता की वस्तु मानना भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को नज़रअंदाज़ करना है। आज भारत हर वर्ष सोने के आयात पर लगभग 70 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर रहा है। यह राशि 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठती है। सरकार के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि इतना बड़ा आयात देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव डालता है। इसी कारण समय-समय पर सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, लोगों से सोना न खरीदने की अपील करती है सोवरेन गोल्ड बांड जैसी योजनाओं के माध्यम से भौतिक सोने की मांग कम करने का प्रयास करती है। लेकिन इस आर्थिक दृष्टिकोण की अपनी सीमाएँ हैं। दिल्ली और मुंबई के वातानुकूलित नीति कक्षों से देखने पर सोना "अनुत्पादक निवेश" लग सकता है, परंतु भारत के गांवों, कस्बों और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यही सोना सबसे विश्वसनीय बैंक है। भारत में करोड़ों लोगों के पास न पर्याप्त बैंक बैलेंस है, न शेयर बाजार में निवेश की क्षमता और न ही बड़े स्तर की औपचारिक वित्तीय पहुंच। उनके लिए घर में रखा सोना ही संकट के समय की पूंजी है। यही कारण है कि आज गोल्ड लोन भारत की अर्थव्यवस्था का एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ स्तंभ बन चुका है। उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय गोल्ड लोन खातों की संख्या लगभग 9 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी करोड़ों परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड लोन आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। यह केवल व्यक्तिगत उपभोग का ऋण नहीं है, बल्कि भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था की कार्यशील पूंजी का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। छोटे दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए, किसान बीज और खाद खरीदने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह छोटे व्यवसाय खड़े करने के लिए, और निम्न आय वर्ग के परिवार अचानक बीमारी, शिक्षा या विवाह जैसे खर्चों के लिए घर का सोना गिरवी रखकर तत्काल ऋण प्राप्त करते हैं। कई छोटे व्यापारी तो बैंक की लंबी प्रक्रियाओं और गारंटी की शर्तों से बचने के लिए गोल्ड लोन को ही सबसे तेज और भरोसेमंद वित्तीय विकल्प मानते हैं। यानी जिस सोने को नीति निर्माता "डेड एसेट" कहते हैं, वही जमीन पर करोड़ों लोगों के लिए "जीवंत तरलता" का स्रोत है। भारत की सामाजिक संरचना को समझे बिना सोने की आलोचना अधूरी है। भारतीय परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए सोना केवल निवेश नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का माध्यम भी है। विवाह, बीमारी, बेरोजगारी या आकस्मिक संकट की स्थिति में सबसे पहले घर का सोना ही परिवार को संभालता है। ग्रामीण भारत में तो यह अनौपचारिक बैंकिंग व्यवस्था का सबसे भरोसेमंद आधार बन चुका है।

ICC ने 2026-27 सत्र के लिए जारी की मैच अधिकारियों की सूची

नितिन मेनन एकमात्र भारतीय अंपायर

नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार (11 मई) के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 2026-27 सत्र के लिए अंपायरों और मैच रेफरियों के एलीट पैनल का ऐलान कर दिया। अंपायरों में नितिन मेनन अकेले भारतीय हैं। आईसीसी ने मैच अधिकारियों की टीम में कोई बदलाव नहीं किया। मेनन 2020 से एलीट पैनल का हिस्सा हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी के एलीट पैनल में अकेले भारतीय हैं। वह भी पहले से ही सूची में थे। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने एक रिलीज में कहा, '2026-27 सीजन के लिए आईसीसी एलीट पैनल में बदलाव न करने का फैसला किया है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंपायरिंग को ऊंचे मानक को दिखाता है।' अंपायर के चयन पैनल में आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान (चेयर), इंग्लिश प्रीमियर लीग के पूर्व रेफरी माइक रिले, पूर्व इंटरनेशनल अंपायर और अंपायर कोच पीटर मैनुअल और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर शामिल थे। इसने मौजूदा पैनल में बदलाव न करने का फैसला करने से पहले अंतराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग और रेफरी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।

आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी (2026-27)
जेफ क्रो (न्यूजीलैंड), रंजन मदुगले (श्रीलंका), एंड्रयू पायक्रॉफ्ट (ज़िम्बाब्वे), रिची रिचर्डसन (वेस्टइंडीज), जवागल श्रीनाथ (भारत)।

आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर (2026-27)
कुमार धर्मसेना (श्रीलंका), क्रिस्टोफर गैफनी (न्यूजीलैंड), एड्रियन होल्डस्टॉक (साउथ अफ्रीका), रिचर्ड इलिंगवर्थ (इंग्लैंड), रिचर्ड केटलबोरो (इंग्लैंड), नितिन मेनन (भारत), अल्लाहुद्दीन पालेकर (साउथ अफ्रीका), अहसान रज़ा (पाकिस्तान), पॉल रीफेल (ऑस्ट्रेलिया), शरफुद्दौला इब्ने शाहिद (बांग्लादेश), रॉडनी टकर (ऑस्ट्रेलिया), एलेक्स व्हार्फ (इंग्लैंड)।

बार्सिलोना ने 29वीं बार जीता ला लीगा का खिताब

● रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया

बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने 'एल क्लासिको' मुकाबले में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराते हुए ला लीगा के खिताब को अपने नाम किया। बार्सिलोना ने यह 29वीं बार ला लीगा की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। रियल मैड्रिड इस मुकाबले में अपने तीन अहम खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी। टीम के स्टार खिलाड़ी काइलियन एम्बाप्पे हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण यह मुकाबला नहीं खेल सके, तो फेडेरिको वाल्वरडे भी इस मैच का हिस्सा नहीं थे। वहीं, वॉर्मअप के दौरान हुई समस्या के कारण डीन हुइजसेन भी यह मैच खेलने नहीं उतरे। बार्सिलोना के लिए इस मुकाबले में पहले गोल की नींव फेरान टोरेस ने रखी। उन्होंने 9वें मिनट में एंटोनियो रुडिगर से फाउल करवाया, जिसके पूरा फायदा मार्कस रैशफोर्ड ने उठाया। रैशफोर्ड की दनदनाती हुई किक को गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। टोरेस ने 18वें मिनट में बार्सिलोना की बढ़त दोगुनी कर दी, जब डैनी ओल्मो ने स्ट्राइकर को स्मार्ट बैकहील से शानदार पास दिया।

ब्रेक से पहले रैशफोर्ड के पास तीसरा गोल करने का शानदार मौका था, जब टोरेस ने उन्हें फिर से गोल करने के लिए बेहतरीन पास दिया, लेकिन इस बार कोर्टोइस ने शॉट को वाइड टिप कर दिया और ओल्मो ने मिले कॉर्नर से अपना शॉट वाइड मार दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में रियल मैड्रिड संघर्ष करती हुई नजर आई, कोर्टोइस ने रैशफोर्ड के खतरनाक क्रॉस को रोका और टोरेस के शॉट का शानदार अंदाज में बचाव किया। जूड बेलिंगहैम का एक गोल ऑफसाइड होने की वजह से रद्द कर दिया गया।

पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार सिक्स

एक साथ तोड़ा कोहली-यशस्वी समेत 4 खिलाड़ी का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स के ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2026 के 55वें मैच में अपनी टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। इस मैच में मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की और प्रियांश ने उनकी पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ ही प्रियांश अब आईपीएल में किसी मैच में पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। उन्होंने विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल समेत 4 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

प्रियांश ने तोड़ा कोहली-यशस्वी समेत 4 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड- प्रियांश आर्या ने आईपीएल के किसी मैच में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्के लगाने वाले बैटर बने। प्रियांश आर्या ने इस लीग में दूसरी बार ये कमाल किया। स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्के लगाने के बाद उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम कर लिया। इससे पहले प्रियांश आर्या ने साल 2025 में मुल्लांपुर में खलील अहमद की गेंद पर पंजाब के लिए ही खेलते हुए पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया था और एक बार फिर से उन्होंने ये कमाल साल 2026 में किया।

प्रियांश ने एक साथ नमन ओझा, विराट कोहली, फिल साल्ट और यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चारों बल्लेबाजों ने आईपीएल में किसी मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने का कमाल एक-एक बार किया है, लेकिन प्रियांश ने ऐसा दूसरी बार करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। वहीं प्रियांश ने आईपीएल की दोनों पारियों को मिलाकर पहली गेंद पर छक्का लगाने का कमाल तीसरी बार किया जबकि उनसे आगे यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने ऐसा 4 बार किया है।

आईपीएल मैच में पहली गेंद पर छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

ब्रैड हॉज (केकेआर) की गेंद पर नमन ओझा (आरआर), डरबन, 2009
वरुण एरोन (आरआर) की गेंद पर विराट कोहली (आरसीबी), बेंगलुरु, 2019
नुवान तुषारा (एमआई) की गेंद पर फिल साल्ट (केकेआर) कोलकाता, 2024
खलील अहमद (सीएसके) की गेंद पर प्रियांश आर्या (पीबीकेएस), मुल्लांपुर, 2025
मिचेल स्टार्क (डीसी) की गेंद पर यशस्वी जायसवाल (आरआर), जयपुर, 2026
मिचेल स्टार्क (डीसी) की गेंद पर प्रियांश आर्या (पीबीकेएस), धर्मशाला, 2026

प्रियांश ने 6 छक्के लगा बनाया खास रिकॉर्ड

वैभव टॉप पर; IPL के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

नई दिल्ली। प्रियांश आर्या ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 55वें मैच में शानदार बल्लेबाजी की और 33 गेंदों पर 56 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 169.70 का रहा। प्रियांश आर्या ने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाने के बाद आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यशस्वी, हेड और जयसूर्या से ऊपर आ गए। प्रियांश ने तोड़ा यशस्वी, हेड और जयसूर्या का रिकॉर्ड, वैभव हैं नंबर 1 प्रियांश आर्या ने दिल्ली के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और अब वो आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। प्रियांश आर्या ने इस सीजन में पावरप्ले में अब तक कुल 26 छक्के लगाए हैं। उन्होंने यशस्वी जायसवाल, ट्रैविस हेड और सनत जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 22-22 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में वैभव पहले नंबर पर 32 छक्के के साथ मौजूद हैं। वैभव इस सीजन में पावरप्ले में अब तक 32 छक्के लगा चुके हैं।

पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

- 32 छक्के : वैभव सूर्यवंशी (2026)
- 29 छक्के : अभिषेक शर्मा (2024)
- 27 छक्के : अभिषेक शर्मा (2026)
- 26 छक्के : प्रियांश आर्या (2026)
- 22 छक्के : यशस्वी जायसवाल (2025)
- 22 छक्के : ट्रैविस हेड (2024)
- 22 छक्के : सनत जयसूर्या (2008)

तीसरी बार पावरप्ले में बनाए 50 प्लस रन

प्रियांश ने दिल्ली के खिलाफ 56 रन की पारी खेली, लेकिन पावरप्ले के दौरान उन्होंने 27 गेंदों पर 50 रन बनाए। आईपीएल में ये तीसरा मौका था कि जब उन्होंने पावरप्ले के दौरान 50 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली। प्रियांश ने एक साथ यशस्वी जायसवाल, इशान किशन, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह समेत 6 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

पावरप्ले में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले भारतीय

- 4 - वैभव सूर्यवंशी
- 3 - प्रियांश आर्या
- 2 - केएल राहुल
- 2 - रिद्धिमान साहा
- 2 - यशस्वी जायसवाल
- 2 - ईशान किशन

दिल्ली ने पंजाब से लिया बदला

दिल्ली कैपिटल्स ने चेस किया 210 का लक्ष्य

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। इस मैदान पर यह मौजूदा सीजन का पहला मुकाबला भी था। पंजाब के लिए यह सीजन का 11वां मैच था जबकि दिल्ली की टीम अपना 12वां मुकाबला खेलने उतरी थी। मैच का टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने और पहले गेंदबाजी का फैसला उन्होंने लिया था।

प्रियांश और अय्यर ने ठोके पचासे- उसके बाद पहले खेलते हुए पंजाब किंग्स को प्रियांश आर्या ने अच्छी शुरुआत दिलाई और 33 गेंद पर 56 रन की पारी खेली। उनके साथी ओपनर और इन फॉर्म बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह 18 रन ही बना पाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 59 रन की पारी खेली। कूपर कोनोली ने 38 और अंत में सूर्यांश शेडगे ने 8 गेंद पर 21 रन ठोकते हुए स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 तक पहुंचा दिया।

एएफसी अंडर 17 एशियन कप: उज्बेकिस्तान से 0-3 से हारकर टूर्नामेंट से

बाहर हुई भारतीय पुरुष टीम

जेद्दा। किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी हॉल स्टेडियम में एएफसी अंडर 17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 के ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में भारत को डिफेंडिंग चैंपियन उज्बेकिस्तान से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। भारत का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में सीधे क्वालीफाई करने का सपना भी अधूरा रह गया। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारने के बाद, भारतीय टीम को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत की जरूरत थी। यही वजह रही कि भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन उज्बेकिस्तान के खिलाफ सावधारी से खेलती हुई नजर आई। हालांकि, उज्बेकिस्तान ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और भारत के डिफेंस का बार-बार परखा। पहले हाफ में दबाव के बावजूद भारत के डिफेंस का प्रदर्शन दमदार रहा। बैकलाइन ने अपनी शेप अच्छी बनाए रखी, जबकि गोलकीपर राजरूप सरकार ने उज्बेकिस्तान के कई प्रयासों को विफल किया। हालांकि, मैच के 32वें मिनट में भारतीय गोलकीपर से बड़ी चूक हुई, जिसका फायदा उज्बेकिस्तान को मिला। दरअसल, उज्बेकिस्तान के आक्रामक खेल को रोकने के लिए गोलकीपर राजरूप अपनी लाइन से बाहर निकले, लेकिन पेनल्टी एरिया में वह उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी लाजिज अब्दुरईमोव को गिरा बैठे। इसके बाद उज्बेकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला और अब्दुरईमोव ने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाते हुए उज्बेकिस्तान को 1-0 की बढ़त दिला ही।

भारतीय टीम ने ब्रेक से पहले गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। गुनलेइबा वांगखेइराकपाम ने गोल के सामने एक शानदार क्रॉस दिया, लेकिन कोई भी भारतीय अटैकर इस शॉट को गोल में तब्दील नहीं कर सका। भारत मैच के 56वें मिनट में स्कोर बराबर करने के काफी करीब पहुंचा। डल्लालमुओन गंगटे ने एक शानदार फ्री-किक मारी जो क्रॉसबार को हिलाकर गोलकीपर को चकमा दे गई।

व्यापार

रुपया फिर रसातल में, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंची कीमत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 35 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 95.63 पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव एवं समझौते की उम्मीदें धूमिल होने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.57 पर खुला और फिर टूटकर सर्वकालिक निचले स्तर 95.63 पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 35 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को 79 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 95.28 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.14 पर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 525.44 अंक टूटकर 75,489.84 अंक पर जबकि निफ्टी 164.5 अंक फिसलकर 23,651.35 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 105.10 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल का भंडार बहुत कम रह गया है। अप्रैल में ओपेक देशों का रोजाना उत्पादन साल 2000 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण कुवैत और इराक जैसे देश एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उनके पास तेल रखने के लिए सुविधा नहीं है। रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 35 पैसे टूटकर ऑल टाइम लो पर पहुंचा अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 105.10 प्रति बैरल पहुंचा शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे।

ऐप्स के जरिए घरेलू काम के लिए बुकिंग में भारी उछाल, वर्कर्स के लिए कंपनियों में मारामारी

नई दिल्ली, एजेंसी। घर के कामकाज के लिए तुरंत हेल्पर मुहैया कराने वाले स्टार्टअप्स कंपनी और मांग में जबरदस्त उछाल आया है। अप्रैल के महीने में इन तीनों ऐप्स की कुल बुकिंग 30 लाख के पार निकल गई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की वजह से मजदूरों की कमी के बावजूद इन कंपनियों ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में इन कंपनियों को करीब 20 लाख बुकिंग मिली थीं। यह अप्रैल में बढ़कर 30 से 31 लाख के बीच पहुंच गई। इस बढ़त की एक बड़ी वजह यह रही कि दो कंपनियों अर्बन कंपनी और स्नैबिट ने अपनी सर्विस के दाम बढ़ा दिए, जिससे उनकी कमाई बढ़ी। प्रोंटो नाम की कंपनी फिलहाल कीमत के मामले में पीछे है, लेकिन उसने हाल ही में करीब 167 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है। इससे उसकी वैल्यू 200 मिलियन डॉलर हो गई है। वहीं, स्नैबिट ने भी अप्रैल में 56 मिलियन डॉलर जुटाए और उसकी वैल्यू 350 मिलियन डॉलर पहुंच गई है। एक अधिकारी ने श्वञ्ज को बताया, मार्च और अप्रैल में मजदूरों की कमी की वजह से काम में कुछ रुकावटें आईं। इस कारण कंपनियों को कुछ इलाकों में दाम बढ़ाने पड़े। इसके साथ ही, वर्कर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कंपनियों के बीच कड़ी होड़ मची रही। कमाई की बात करें तो अर्बन कंपनी को हर ऑर्डर पर औसतन 180-200 रुपये मिले, जबकि स्नैबिट को 160-180 रुपये। प्रोंटो की कमाई प्रति ऑर्डर 80-100 रुपये रही। क्योंकि वह अपने ग्राहकों को 30 मिनट के सस्ते पैक ऑफर करती है।

60 दिनों का पेट्रोल-डीजल और 45 दिनों की रसोई गैस बाकी

सरकार ने कहा- चिंता करने की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में कारण के कारण दुनियाभर में कच्चे तेल का संकट पैदा हो गया है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार है। देश में फिलहाल 60 दिनों का तेल भंडार, 60 दिनों का प्राकृतिक गैस भंडार और 45 दिनों का रसोई गैस भंडार उपलब्ध है। सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि फ्यूल सप्लाई की राशनिंग की कोई योजना नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते आयात पर असर पड़ा है। इसके बावजूद एलपीजी का भी पूरा इंतजाम किया गया है और घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी सप्लाई की जा रही है। तेल और गैस मंत्रालय में सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। युद्ध के बावजूद करीब 60 दिनों का पेट्रोल-डीजल का भंडार है और लगभग 45 दिनों का एलपीजी भंडार मेंटेन किया जा रहा है। विभिन्न देशों से खरीद बढ़ाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर बना हुआ है। साथ ही सरकार ने बताया कि भारत तेल शोधन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक भी है। भारत वर्तमान समय में 150 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है तथा घरेलू मांग भी पूरी की जा रही है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत 150 से अधिक देशों को निर्यात करता है और घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा कर रहा है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर गठित मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत में पिछले 70 दिनों से पेट्रोलियम कीमतों को स्थिर रखा गया है, जबकि कई देशों में कीमतों में 30 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय तेल कंपनियां प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नुकसान करीब 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है। इसके बावजूद सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ आम नागरिकों पर न पड़े। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में ईंधन संरक्षण केवल तत्काल बचत के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की दीर्घकालिक क्षमता निर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि संकट लंबा चलता है तो अपनी तैयारी बनाए रखने के लिए अभी से जिम्मेदार तरीके से खपत की संस्कृति विकसित करना आवश्यक है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)